सुबह सवेरे

A Daily News Magazine

भोपाल

गुरुवार, 24 अप्रैल, 2025

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 224, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

पहली बात

दरिन्दगी: आतंकवादियों ने कश्मीरियों के पेट पर लात मारी

उमेश त्रिवेदी
प्रधान संपादक

पहलगाम के निकट पर्यटकों पर दहला देने वाले आंतकवादी हमले के बाद देश के भीतर-बाहर सुलगने वाली चिंगारियों के धुँए में कई साजिशें आकार लेती महसूस हो रही हैं। पाक-सेना व्दारा प्रायोजित हमले की टाइमिंग अपने आप काफी कुछ बयान करती है। साजिश का एक पहलू यह है कि भारत में सियासी खलल पैदा होने के साथ ही धार्मिक उन्माद और दरार गहरा जाए। दूसरा, भारत के दूसरे हिस्सों में कश्मीर के प्रति बढ़ता रूझान मुरझा जाए और देश के पर्यटक कश्मीर की खूबसूरत वादियों की बारे में सोचना भी छोड़ दें। तीसरा, पाकिस्तानी जनता में पाक सेना के प्रति बढ़ते आक्रोश का दावानल भारत की ओर मुड़ जाए। साजिशों के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी विदेश यात्रा को अधूरी छोड़कर स्वदेश लौट आए हैं एवं गृहमंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में मोर्चा संभाल लिया है।

बहरहाल, आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान और आतंकवादियों के मंसूबे भारत के सियासी गलियारों में फलीभूत होते नजर नहीं आ रहे हैं। देश के सभी सियासी दलों की प्रतिक्रियाओं की एक अनुगूंज है कि इस मामले में हम एक हैं। हमले के विरोध में जम्मू-कश्मीर में स्वःस्फूर्त राज्यव्यापी बंद ने कश्मीरी अवाम के मंसूबों को साफ कर दिया है कि वो इस आतंकवाद को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। लोकसभा में नेता-प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर बात करके पूरा समर्थन जाहिर किया है। कांग्रेसाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यह देश पर सीधा हमला है, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना जाहिए। उन्हे विश्वास है कि केन्द्र सरकार विपक्षी दलों को विश्वास मे लेकर आतंकवाद के मामले मे ठोस कार्रवाई करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है। सरकार इस मामले में कठोर कारवाई करेगी।

इसके अलावा हुर्रियत कांफ्रेंस जैसा संगठन भी कश्मीर बंद में स्थानीय सियासी दलों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। सत्ताधारी नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी, पीपुल्स पार्टी,समेत घाटी की सभी सियासी पार्टियाँ एक जूट नजर आ रही हैं। कश्मीर में यह सियासी एकता अभूतपूर्व है। 27 बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने की दरिन्दगी के साथ ही आतंकवादियों ने कश्मीरी-अवाम के पेट पर लात मारी है, जिसकी हिफाजत की वह बात करते हैं।

कश्मीरी मामलों के जानकारों का मत है कि पाकिस्तानी सेना व्दारा प्रायोजित यह हमला ऐसे वक्त हुआ है, जब जम्मू-कश्मीर में अपेक्षाकृत शांति है, बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं। पर्यटन में तेजी आई है। जबकि, पाकिस्तान की सियासत में सेना सवालों में घिरी है। पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठान आंतरिक जांच का सामना कर रहे हैं और तेजी से उभर रहे आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से निपटने में अक्षम सिद्ध हो रहे हैं। इन मुद्दों पर सेना और सैनिक प्रतिष्ठानों पर जबरदस्त दबाव है। इस संदर्भ में कश्मीर मुद्दे का कोई भी अंतरराष्ट्रीयकरण पाकिस्तानी सेना पर उसके घरेलू जनमत के दबाव को कम कर सकता है। साथ ही अवाम के दबाव के प्रवाह को भारत-विरोध में तब्दील कर सकता है। पाकिस्तान मानता है कि तहरीके-ए-तालिबान पाकिस्तान को भारत बढ़ावा दे रहा है।

पहलगाम आतंकवादी हमले को कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया है कि भारत में सांप्रदायिकता सुलग उठे और बढ़ते पर्यटन के माध्यम से कश्मीर में आने वाली आर्थिक खुशहाली दम तोड़ने लगे। तीस पर्यटकों की मौत के लिए जिम्मेदार इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा की शाखा 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (टीआरएफ) ने ली है। टीआरएफ और पाकिस्तान के रिश्ते जगजाहिर हैं। इस हमले में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का 16 अप्रैल का वह भाषण भी गौरतलब है, जिसमें उन्होनें कश्मीर को पाकिस्तान के 'गले की नस' कहा था। पाक सेनाध्यक्ष के इस भाषण को भारत ने पूरी तरह खारिज कर दिया था। जनरल मुनीर ने कहा था कि 'यह हमारे गले की नस थी, यह हमारे गले की नस है, हम इस कभी भी नहीं भूलेंगे।' 'कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरी भाइयों के संघर्ष में पाकिस्तान कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, हम उनके साथ खड़े रहेंगे।' पहलगाम में आतंकी हमले को जनरल मुनीर के साथ दिन पुराने भाषण से जोड़ कर ही देखा जा रहा है।

पहलगाम में आतंकवादी हमले में 27 पर्यटकों मौत ने समूची कशमीर-घाटी को उव्देलित कर दिया है। जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलो मे पर्यटकों को कभी भी निशाना नहीं बनाया जाता था। क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री ही कश्मीरियों की रोजी-रोटी का मुख्य जरिया रहा है। वह घाटी में रहने वाले लाखों कश्मीरियों की संजीवनी है। पर्यटन का कश्मीर की अर्थ व्यवस्था में कितना महत्व है, वह इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 में जम्मू-कश्मीर की कुल स्टेट जीडीपी में 8.47 फीसदी हिस्सेदारी केवल पर्यटन की थी। वर्ष 2023 में कश्मीर में 1 करोड़ 43 लाख से ज्यादा पर्यटक आए। हर साल यह संख्या बढ़ रही थी। कश्मीर के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद न केवल लोगों को धरती के स्वर्ग में होने का अहसास कराता है बल्कि पर्यटक यहां आकर भारत के मुकुट का हिस्सा बनकर गौरवान्वित होते रहे हैं। लेकिन करीब तीन दशकों तक आंतक की चपेट में रहे जम्मू कश्मीर में टूरिज्म भी बहुत प्रभावित हुआ। इसका अहसास हर आम कश्मीरी को है। लेकिन 6 साल पहले जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद वहां सामान्य होते हालात की बदौलत पटरी पर आते टूरिज्म पर यह आतंकी हमला गाज बन कर गिरा है। इससे उबरने में वर्षों लग जाएंगे। इस हमले ने कश्मीर में टूरिज्म को वर्षों पीछे ढकेल दिया है।

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

मौसम-ए-गुल पर ख़िज़ाँ का
ज़ोर चल जाता है क्यूँ
हर हसीं मंज़र बहुत जल्दी
बदल जाता है क्यूँ
यूँ अँधेरे में दिखा कर
रौशनी की इक झलक
मेरी मुट्ठी से हर इक जुगनू
निकल जाता है क्यूँ
रौशनी का इक मुसाफ़िर
थक के घर आता है जब
तो अंधेरा मेरे सूरज को
निगल जाता है क्यूँ
तेरे लफ़्ज़ों की तपिश से
क्यूँ सुलग उठती है जाँ
सर्द-मेहरी से भी तेरी
दिल ये जल जाता है क्यूँ
अब के जब लौटेगा वो तो
फ़ासला रक्खेंगे हम
ये इरादा उस के आते ही
बदल जाता है क्यूँ
दूर है सूरज 'अलीना'
फिर भी उस की धूप से
बर्फ़ की चादर में लिपटा
तन पिघल जाता है क्यूँ।

– अलीना इतरत

सब कुछ थमा, अशांत हो गई बैसरन घाटी

पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले

***भारत ने सिंधु जल समझौता रोका, *दूतावास बंद**
***पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द, *48 घंटे में देश छोड़ें**
***एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद**

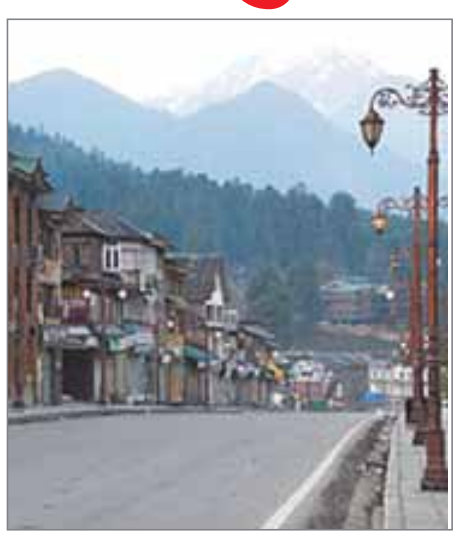

पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाएं हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग में 5 बड़े फैसले लिए गए। यह सीसीएस की बैठक ढाई घंटे चली। इसमें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अित डोभाल समेत कई अफसर मौजूद रहे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया, पहलगाम आतंकी हमले की गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट सुरक्षा समिति (सीसीएस) ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। भारत ने सिंधु जल समझौता रोका, दूतावास बंद; पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द, कहा- 48 घंटे में देश छोड़ने को कहा है, एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद।

28 पर्यटकों का खून माफ नहीं करेगा हिंदुस्तान

प्रधानमंत्री ने कहा-

उनका नापाक मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा – पीएम मोदी ने कहा– पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस घिनौने कृत्य के पीछे जो भी लोग हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और यह और भी मजबूत होगा।

● जांच में खुलासा-पहलगाम हमले में 2 लोकल, 3 पाकिस्तानी आतंकी शामिल ● पाक को सबक सिखाने की तैयारी...पीएम निवास में बैठक, शाह, राजनाथ, डोभाल मौजूद ● पहलगाम अटैक के 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी

श्रीनगर/नईदिल्ली (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों ने बर्बरता दिखाते हुए निर्दोष पर्यटकों को नाम और धर्म पूछकर गोलियों से भून डाला। आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है, तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवादियों को कड़ी सबक सिखाने की तैयारी में जुट गई है। 27 पर्यटकों का खून माफ नहीं करेगा हिंदुस्तान और आतंकियों और उसके आका पाक को सबक सिखाने की तैयारियां शुरु होगई थी। सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री आवास में जारी थी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ, एनएसए अजित डोभाल मौजूद हैं। जम्मू-कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। हमले के कुछ देर बाद श्रीनगर पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पहलगाम का एरियल सर्वे किया और बैसरन में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स के एक कार्यक्रम में कहा- पहलगाम हमले के विरोध में जोरदार तरीके से एक्शन नजर आएगा। आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उचित समय पर भारत जवाब देगा।

दरिंदों के स्केच जारी

सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबु तल्हा बताए गए हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि हमले का मास्टर माइंड लश्कर-ए तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जो पाकिस्तान में मौजूद है। इधर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी जांच के लिए पहलगाम पहुंच गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमले में 5 आतंकी शामिल थे। इनमें से दो लोकल और 3 पाकिस्तानी आतंकी थे। पुलिस ने पूछताछ के लिए सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया है।

राष्ट्रपति समेत कई नेता, अभिनेताओं, खिलाड़ियों ने गहरा दुख जताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, असदुद्दीन ओवैसी, अक्षय कुमार, समेत कई नेता और सेलेब्रिटीज ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और दुख वयक्त किया है...। राष्टपति मुर्मू ने कहा- यह एक नृशंस और अमानवीय कृत्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस हमले पर दुख जताया है।

अमित शाह ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शाह बैसरन घाटी पहुंचे। यहां उन्होंने हमले के पीड़ितों से बातचीत की और अधिकारियों से जानकारी ली। उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दो दिन दौरा छोड़ बुधवार सुबह भारत लौट आए हैं। वे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक करेंगे। शाह ने हमले में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे का एलान, गृहमंत्री ने की घायलों से मुलाकात की।

घाटी हुई रक्तरंजित– पेज 2 पर देखें

देश में सर्वाधिक 2600 रूपये प्रति क्विंटल दर पर गेहूं खरीद रही है मध्यप्रदेश सरकार

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार पूरे देश में सर्वाधिक 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं खरीद रही है, ताकि प्रदेश के गेहूं उत्पादक किसानों को सर्वाधिक लाभ मिले। इस उपार्जन राशि में सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस राशि भी शामिल है। उन्होंने कहा कि गेहूं उत्पादन एवं उपार्जन के मामले में हम पंजाब और हरियाणा जैसे खाद्यान्न उत्पादक राज्यों से भी आगे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी प्रकार के राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मंत्रालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता अधिकार संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी प्रकार के राशन कार्ड धारकों को समय पर और बिना किसी कठिनाई के पात्रतानुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को राशन पाने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए व्यवस्थाओं को बेहतर और त्रुटिरहित बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी राशन पाने से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित से जुड़ी सभी योजनाएं, विशेषकर खाद्यान्न वितरण, उज्जवला गैस योजना की सब्सिडी वितरण और घर-घर घरेलू गैस पाइप लाइन डालने का काम पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ किये जाएं, ताकि प्रदेश के नागरिकों को सरकार की सुविधाओं का भरपूर लाभ मिल सके।

हर जरूरतमंद तक खाद्यात्र पहुंचाना हमारी प्राथमिकता– मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि त्रुटिरहित राशन वितरण, किसानों को उपार्जन राशि का समय पर भुगतान और हर जरूरतमंद तक खाद्यान्न पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

गेहूं उपार्जन का काम 5 मई तक पूरा कर लें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में चल रही गेहूं उपार्जन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीदी प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता का पालन किया जाए और किसानों को गेहूं उपार्जन का भुगतान कम से कम समय में कर दिया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग की अवधि 30 अप्रैल तक करें। इस अवधि तक बुकिंग कराने वाले सभी किसानों से गेहूं उपार्जन का समस्त कार्य 5 मई 2025 तक हर हाल में पूराकिया जाए।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बैठक में बताया कि गोदामों में खाद्यान्न स्कंध की हेरा-फेरी पर अंकुश लगाने के लिए अब खाद्य विभाग द्वारा खाद्यान्नों के सभी बारदानों (बोरों) में क्यूआर कोड लगाये जायेंगे। इसी तरह एमपी वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के अधीन सभी वेयरहाउस को भी क्यूआर कोडयुक्त किया जा रहा है। इनमें सीसीटीव्ही कैमरे भी लगवाये जाएंगे। खाद्यान्न वितरण, शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर नजर रखने एवं फूड-स्टॉकिंग के सभी कामों की मुख्यालय से निगरानी के लिए भोपाल में एक कंट्रोल कमांड सेंटर भी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग स्वयं के 1596 गोदामों का क्रमबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण एवं उन्नयन कर रहे हैं।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 22 °c

न्यूनतम 16°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ गुरुवार, 24 अप्रैल 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

- दरिंदों ने कश्मीर में जात नहीं, धर्म पूछा, नाम पूछकर मारी गोली
- अपनों की लाशों के बीच रोते-बिलखते रहे पर्यटक
- पहलगाम हमले का देशभर में विरोध

मिनी स्विटजरलैंड के नाम से प्रसिद्ध बैसरन घाटी हुई रक्तरंजित

सबकुछ अच्छा था। कई नवविवाहित जोड़े भी इनमें शामिल थे, जिनमें से एक नेवी का अधिकारी भी था जिसकी 16 अप्रैल को शादी हुई थी। सबकुछ खुशनुमा था, तभी चार-पांच लोग पुलिस की वर्दी में वहां पहुंचे और पर्यटकों से पंजाबी में बात करने लगे, उनसे उनका नाम पूछा और फिर गोली मार दी।

दोपहर का वक्त था और मिनी स्विटजरलैंड के नाम से प्रसिद्ध बैसरन घाटी में टूरिस्ट मौसम का मजा ले रहे थे। वे वहां के कैंप में पर्यटक घुड़सवारी कर रहे थे। इस इलाके तक पैदल ही पहुंचा जा सकता है। सबकुछ अच्छा था। कई नवविवाहित जोड़े भी इनमें शामिल थे, जिनमें से एक नेवी का अधिकारी भी था जिसकी 16 अप्रैल को शादी हुई थी। सबकुछ खुशनुमा था, तभी चार-पांच लोग पुलिस की वर्दी में वहां पहुंचे और पर्यटकों से पंजाबी में बात करने लगे, उनसे उनका नाम पूछा और फिर गोली मार दी। चीख-पुकार के बीच बूढ़े-बच्चे सभी डरे हुए थे और जान बचाने की जद्दोजहद थी। पीड़ितों के बयान डराने वाले हैं। एक महिला ने तो पति की मौत पर खुद को भी मारने को कहा-तो आतंकियों ने कहा, तुम्हें नहीं मारेंगे, सरकार को बताओ जाकर तुम।

अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करना चाहते हैं आतंकवादी

पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उसकी जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। जब से जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया है, यह आतंकी संगठन सक्रिय है। आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेते हुए भी यह दावा किया गया है कि जिन बाहरियों को कश्मीर में बसाया गया है, उसके खिलाफ यह हमला है। दरअसल टीआरएफ जम्मू-कश्मीर के लगातार सुधरते हालात से परेशान है, क्योंकि उसका आका पाकिस्तान यह नहीं चाहता कि कश्मीर और कश्मीरी खुशहाल हो। आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर में स्थिति लगातार सुधर रही है, चुनाव अच्छे से संपन्न हो रहे हैं, कोई बहिष्कार नहीं हो रहा, यह बात पाकिस्तान को खटक रही है। बस इसी स्थिति को खराब करने के लिए उसने अपने पिछलग्गुओं से टूरिस्टों पर हमला करवाया है, ताकि टूरिस्ट यहां आने से डरें और कश्मीरियों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़े। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी भारत दौरे पर उन्हें भी आतंकी अपनी ताकत दिखाकर कश्मीर के मसले को एक बार फिर वैश्विक स्तर पर उठाना चाहते हैं। वहीं संभवत : आतंकी अमरनाथ यात्रा को भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जो कुछ महीनों बाद शुरू होने वाली है और पहलगाम अमरनाथ यात्रा का बेसकैंप है।

टोपी और दाढ़ी का नाम इस्लाम नहीं, पाकिस्तान के इरादों का जवाब दे सरकार

1947 में जब भारत आजाद हुआ, उस वक्त पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में साथ नहीं रह सकते, इसलिए टू नेशन का एजेंडा चलाया गया और आज तक उस एजेंडे का दुष्प्रभाव भारत झेल रहा है। कश्मीर पर पाकिस्तान की नजर शुरू से रही है और जब पाकिस्तान उसके साथ नहीं गया, तो वह छद्म तरीके से इसे हथियाने की कोशिश में लगा रहता है। पाक अधिकृत कश्मीर बेहाल है, जबकि हमारे जम्मू-कश्मीर में खुशहाली है। हमारे यहां विधानसभा है, लोकसभा के चुनाव होते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद से तो यहां सैलानी भी खूब आ रहे हैं, जिससे कश्मीर की आय में वृद्धि हुई है। बस यही बात पाकिस्तान को अखर रही थी और उसने सैलानियों को ही निशाना बनाया, ताकि एक तीर से दो शिकार हो जाएं, यानी सैलानी डर से ना आएं, तो कश्मीरियों पर असर पड़ेगा और दूसरे धर्म के आधार पर सैलानियों को मारने से देश में नफरत बढ़ेगी।

- **पाक ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कश्मीर को किया अशांत-** पहलगाम में मंगलवार को जिस तरह की बर्बरता हुई, उसके तार सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़े हैं। अपने देश की नाकामियों को छिपाने और अपनी जनता के बीच लोकप्रियता हासिल करने के लिए पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकत कई बार करता रहा है। अपनी मंशा को प्रकट करते हुए हाल ही में पाक के सेना अध्यक्ष असीम मुनीर ने यह कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। आतंकियों ने उसी पैटर्न पर काम करते हुए धर्म पूछकर सैलानियों को मारा। उनका एजेंडा है देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत के बीज बोना।
- **पहलगाम अटैक की तैयारी पहले से कर रहा था पाकिस्तान-** पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से जम्मू-कश्मीर की शांति भंग करने की योजना बना रहा था। पीओके में इस साल की शुरुआत से ही जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी सक्रिय थे। जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वे कश्मीर की शांति भंग करने के फिराक में थे।

सेनाध्यक्ष असीम मुनीर ने भी यह स्पष्ट कर दिया था कि वे कश्मीर को अशांत करना चाहते हैं और इसके लिए उसने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया था। वरिष्ठ पत्रकार अनिल आनंद ने बताया कि मैं जम्मू-कश्मीर का ही रहने वाला हूं। मंगलवार को पहलगाम में जो कुछ हुआ, उसकी शुरूआत तीन-चार महीने पहले से कुछ घटनाओं के रूप में हो चुकी थी। जम्मू और पंजाब के बीच कठुआ जिला है, जहां से होकर रावी नदी बहती है, इसी को घुसपैठियों ने अपना रास्ता बनाया और यहां घुसे। इनका एजेंडा है जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाकर भारत को अशांत करना और अपने देश में लोकप्रियता हासिल करना।

पाकिस्तानियों के पास तो कश्मीर के अलावा और कोई राग है नहीं और वे हमेशा इसी राग को अलापते रहते हैं।

पाकिस्तान का बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत आदि कुछ ऐसे इलाके हैं, जहां अलगाववादी सक्रिय हैं। इन इलाकों में अलग राज्य की मांग हो रही है। पाकिस्तान की सरकार इन मुद्दों से अपने देश का ध्यान भटकाना चाहती है, क्योंकि वो इन इलाकों में नकारा साबित हो चुकी है।

आतंकी हमले में 7 मौतों की मार्मिक कहानी

कानपुर-जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और कानपुर के शुभम को पत्नि के सामने गोली मार दी। दोनों की हाल ही में शादी हुई थी। वे हनीमून और घूमने के लिए पहलगाम आए थे।

हमले में इंदौर के कारोबारी सुशील नथानियल, जयपुर के नीरज, रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया, बिहार के आईबी अफसर मनीष रंजन और गुजरात के भी 3 लोग मारे गए। दिनेश अपनी सालगिरह मनाने गए थे।

यूपी- आतंकियों ने पत्नी के सामने मारी शुभम को गोली, फिर बोले- तुम मोदी-सरकार को जाकर बताओ

आतंकियों ने कानपुर के रहने वाले शुभम को पत्नी एशान्या के सामने गोली मार दी। एशान्या चीख-चीखकर रोते हुए आतंकियों से बोलती हैं- मुझे भी गोली मार दो। इस पर आतंकी कहते हैं- हम आपको गोली नहीं मारेंगे, आप सरकार को जाकर बताओ। यह बात एशान्या ने खुद परिवार के लोगों को बताई। शुभम और उनकी पत्नी के साथ उनके परिवार के 11 लोग जम्मू-कश्मीर घूमने गए थे

म.प्र. - इजराइल जाना था, लंबी छुट्टी नहीं मिली तो कश्मीर गए, बिना बताए गए थे इंदौर के सुशील, लौटकर सरप्राइज देना चाहते थे

मप्र- भैया-भाभी और उनके दोनों बच्चे जम्मू-कश्मीर घूमने गए थे। हमें पता नहीं था। कल शाम करीब 8 से 9 बजे के बीच भतीजे ऑस्टिन का फोन आया। उसका रो-रोकर बुरा हाल था। कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। दो बार फोन काट दिया। तीसरी बार में उसने बताया कि आतंकवादियों ने पापा को गोली मार दी है। बहन आकांक्षा के पैर में भी गोली लगी है। मां और मैं जैसे-तैसे बचे हैं। भतीजे की बात सुनकर हमारे भी हाथ-पैर ढीले पड़ गए। यह कहते हुए पहलगाम में मारे गए एलआईसी अफसर सुशील नथानियल के ममेरे भाई संजय कुमरावत फूट-फूटकर रोने लगे। कहा, मेरा दोस्त जैसा भाई चला गया। सुशील को सरप्राइज देने की आदत थी, इसीलिए उसने इस टूर के बारे में हमें नहीं बताया। वहां से लौटकर हमें सरप्राइज देना चाहता था। वह सरप्राइज देकर ही हमसे विदा हो गया। लेकिन उसने इस बार समय गलत चुन लिया। संजय ने कहा, कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से ही हम लोग वहां घूमने का प्लान बना रहे थे। लेकिन वहां के हालात ठीक नहीं हैं। यदि सुशील ने हमें पहले बताया होता या चर्चा की होती तो हम जाने ही नहीं देते।

बिहार- आईबी अफसर की मौत, पत्नी-बच्चों के सामने मारी गोली, हैदराबाद में पोस्टेड थे

आतंकी हमले में बिहार के रहने वाले मनीष रंजन की भी मौत हुई है। रंजन पिछले 2 सालों से आईबी के हैदराबाद ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर के पद पर पोस्टेड थे। मनीष को उनकी पत्नी और 2 बच्चों के सामने गोली मार दी गई। रंजन की पत्नी आशा देवी और बच्चे सुरक्षित हैं। मनीष रोहतास के करगहर थाना क्षेत्र के अरुही गांव के रहने वाले थे।

- **राजस्थान- जयपुर यूएई में करते थे जॉब, पत्नी के साथ कश्मीर घूमने गए थे-** जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जयपुर का युवक भी मारा गया। युवक का नाम नीरज उधवानी है। नीरज (33) यूएई में जॉब करते थे। करीब दो साल पहले पुष्कर के भंवर सिंह पैलेस में शादी हुई थी। वे 4 दिन पहले ही जयपुर आए थे। इसके बाद तीन दिन पहले पत्नी के साथ जयपुर से कश्मीर घूमने गए थे। हमले के समय पत्नी होटल में थी।
- **गुजरात- भावनगर के पिता-पुत्र और सूरत के एक युवक को आतंकियों ने मारी गोली-** पहलगाम आतंकी हमले में गुजरात के तीन लोगों की मौत हुई है। मंगलवार को सूरत के शैलेशभाई हिम्मतभाई कलथिया की, जबकि भावनगर के यतीशभाई और उनके बेटे स्मित की आज बुधवार को मौत की पुष्टि हुई। भावनगर से 20 लोगों का एक ग्रुप जम्मू-कश्मीर गया था, जिसमें भावनगर के कालियाबीड़ क्षेत्र में रहने वाले यतीशभाई परमार, उनकी पत्नी काजलबेन और बेटा स्मित यतीशभाई शामिल थे। आतंकियों ने काजलबेन को छोड़ दिया, जबकि उनके पति और बेटे को गोली मार दी।

सैनिक कल्याण कार्यों में सेवा और सम्मान का भाव रहे : राज्यपाल

● **राजभवन में समामेलित विशेष निधि प्रबंध समिति की 24वीं बैठक सम्पन्न**

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि सैनिक कल्याण कार्यों में सेवा और सम्मान का भाव रहना चाहिए। इसी के अनुरूप सैनिक कल्याण कार्यों का विस्तार और स्वरूप निर्धारित किया जाना चाहिए। कार्य संचालन में सैनिकों के प्रति सम्मान और सेवा के भाव और भावनाएं आदर्श रूप में प्रतिध्वनित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए किए जाने वाले निर्माण कार्य की डिजाइनिंग, आकार और सुविधाएं पूर्व सैनिकों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई जाए। कार्य की समय सीमा और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। राज्यपाल श्री पटेल राजभवन में समामेलित विशेष निधि प्रबंध समिति की 24वीं बैठक की अध्यक्षता कर संबोधित कर रहे थे।

बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव गृह श्री जे. एन कंसोटिया राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री के.सी. गुप्ता, जनरल आफिसर कमांडिंग मध्य भारत एरिया लेफ्टिनेंट जनरल पी.एस. शेखावत और जनरल ऑफिसर कमांडिंग पश्चिम मध्यप्रदेश सब एरिया मेजर जनरल सुमित कबथियाल उपस्थित थे।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि सैनिक कल्याण संबंधी भवनों और निर्माण कार्यों की डिजाइनिंग में उपयोगकर्ता और आगंतुकों की जरूरतों के साथ सामंजस्य पर विशेष बल दिया जाए। उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण विश्राम गृह भोपाल के नवीनीकरण का प्रस्ताव शीघ्र तैयार किया जाए। प्रस्ताव केन्द्र सरकार को समय सीमा में भेजना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर के सैनिक विश्राम गृहों के नवीनीकरण की रूपरेखा पर अपर मुख्य सचिव गृह, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव और सचिव वित्त की समिति द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण करने के निर्देश दिए है। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार ने शहीदों के माता-पिता को दी जाने वाली अनुदान राशि में वृद्धि की है। अब शहीद के माता-पिता को अनुदान की राशि 10 हजार रुपए दी जाएगी। मध्यप्रदेश के निवासी ऐसे माता-पिता, जिनकी पुत्री सशस्त्र सेना में है, उनकी सम्मान निधि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए प्रतिवर्ष की गई है।

बैठक में पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर खड़की पुणे को प्रदेश के मूल निवासी दो सैनिक को दवाई और देख-रेख के लिए प्रति पूर्व सैनिक एक लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वीर नारी पुत्री के विवाह के लिए अनुदान राशि को 45 हजार से बढ़ाकर 1 लाख करने का निर्णय किया गया है। इस अवसर पर समामेलित विशेष निधि प्रबंध समिति सदस्य मेजर जनरल सेवानिवृत्त निश्चय राउत, मेजर जनरल सेवानिवृत्त पी.के. त्रिपाठी, संयुक्त संचालक केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल श्री प्रशांत मिश्रा एवं संचालक राज्य सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त श्री अरुण नायर सहित प्रशासन और सेना के अधिकारी मौजूद थे।

4 हजार ग्रामों और 356 शहरी वार्डों में योग समितियों का गठन

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा योग के प्रति जागरूकता और प्रचार-प्रसार का कार्य किया जा रहा है। इसके लिये मध्यप्रदेश योग आयोग का गठन भी किया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह योग आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रदेश के 52 जिलों में जिला योग समितियां और 313 विकासखंडों में विकासखंड योग समितियों के गठन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इन जिलों में लगभग 4 हजार ग्रामों में और शहरी क्षेत्र के 356 वार्डों में योग समितियों का गठन किया गया है।

योग आयोग पोर्टल- मध्यप्रदेश योग आयोग का पोर्टल तैयार कर एनआईसी पर संचालित किया जा रहा है। पोर्टल पर योग आयोग की समस्त जानकारियां, जिला योग प्रभारियों एवं विकासखंड योग प्रभारियों की व्यक्तिगत जानकारी, योग से निरोग कार्यक्रम में सहयोग देने वाले योग शिक्षकों की जानकारी को प्रदर्शित है। मुख्यमंत्री जिला योग प्रशिक्षण केन्द्रों के सुव्यवस्थित संचालन के लिये उपयुक्त भवन और भूमि उपलब्ध कराने के लिये कलेक्टर्स को पत्र लिखा गया है। वर्तमान में 14 जिलों ग्वालियर, मुरैना, दतिया, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, देवास, नीमच, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, दमोह और शहडोल में मुख्यमंत्री जिला योग प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हो रहे हैं।

स्कूल छात्र-छात्राओं के लिये तैयार किया गया प्रोटोकॉल- स्कूल के छात्र-छात्राओं के लिये 10 मिनट का प्रोटोकॉल मध्यप्रदेश योग आयोग द्वारा तैयार किया गया है। इसमें आसन, प्राणायाम एवं ध्यान शामिल किये गये हैं। प्रोटोकॉल जिला योग प्रभारियों को विद्यालयों में प्रार्थना सत्र के दौरान अभ्यास कराने के लिये उपलब्ध करा दिया गया है। जिलों में गठित योग समितियों द्वारा संचालित निःशुल्क योग कक्षा के लिये एक घंटे का योगाभ्यास प्रोटोकॉल तैयार कर संबंधित एजेंसी को उपलब्ध कराया गया है, जिसके आधार पर योग समितियों द्वारा संचालित निशुल्क योग कक्षाओं में आम नागरिकों को योगाभ्यास कराया जा रहा है। संस्था की पूरे वर्ष की योग गतिविधियों का वार्षिक योग पंचांग आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाता है। जारी कैलेण्डर के अनुसार प्रदेश में योग गतिविधियां संचालित हो रही हैं। प्रदेश में 21 जून 2025 को मनाये जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं।

रेंडम सेना के ट्वीट ने भोपाल पुलिस की नींद उड़ाई

भोपाल (नप्र)। रेंडम सेना नाम के एक्स अकाउंट से किए एक ट्वीट ने भोपाल पुलिस की नींद उड़ा दी। दरअसल इस ट्वीट के साथ एक युवक का फोटो शेयर किया गया था। इस युवक को भोपाल का होने के साथ ही कश्मीर में निर्दोषों की जान लेने वाला मास्टर माइंड बताया गया। इस ट्वीट में भोपाल पुलिस कमिश्नर को टैग किया गया था।

जिसके बाद मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात एक्टिव हुई पुलिस ने फोटो में दिख रहे संदेही को हिरासत में ले दिया। हिरासत में लिए शख्स का नाम जीशान अली बताया गया, जो कोहेफिजा का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास मिले मोबाइल की बारीकी से पड़ताल की। जीशान से करीब पांच घंटे तक पूछताछ की जाती रही।

बुधवार सुबह युवक को हिरासत से रिहा कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को भोपाल पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और बताया कि जीशान द्वारा किसी संदिग्ध गतिविधि में शामिल रहने की जानकारी नहीं मिली है। उसके मोबाइल में भी कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है। पहलगाम घटना से उसका किसी प्रकार का लेना-देना नहीं निकला है।

डिजिटल अरेस्ट में कोर्ट का निर्णय

68 लाख 49 हजार की ठगी करने वाले सगे भाइयों की जमानत अर्जी खारिज

भोपाल (नप्र)। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार शर्मा की अदालत ने विदेशी साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले आरोपियों विशाल भट्ट और यशपाल भट्ट की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह दोनों सगे भाई राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा के निवासी हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने कमीशन लेकर विदेशी साइबर ठगों को भारतीय बैंक खाते उपलब्ध कराए थे, जिससे वे एक व्यक्ति से 68 लाख 49 हजार रुपए की ठगी कर सके।

जानकारी के अनुसार आरोपियों ने एक वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित मनोज भुरारिया को यह विश्वास दिलाया था कि वह आरबीआई और मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं और उनके खिलाफ ताईवान से भेजे जा रहे ड्रग्स के आरोप में कार्रवाई हो रही है। पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट कर विभिन्न खातों में रुपए जमा करने के लिए मजबूर किया गया था।

पूछताछ में आरोपी यशपाल भट्ट ने पुलिस को बताया कि-वह और उसका भाई विशाल खाताधारकों को अधिक पैसे कमाने का लालच देकर उनके बैंक खाते खरीदते थे, जिन्हें बाद में साइबर ठगों को बेच देते थे। दोनों आरोपियों को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

मनोज भुरारिया ने 31 जनवरी 2024 को क्राइम ब्रांच थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 24 जनवरी 2024 को उसे फोन कॉल आया था, जिसमें मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी के नाम से उसे झांसा दिया गया। इसके बाद उसे विभिन्न खातों में कुल 68 लाख 49 हजार रुपए जमा करने के लिए कहा गया। बाद में पीड़ित ने यह मामला पुलिस में दर्ज कराया, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

डिजिटल एम.बी. के माध्यम से ही होगा वेंडर कांट्रेक्टरों का भुगतान : ऊर्जा मंत्री तोमर

एम.पी. ट्रांसको का डिजिटाइजेशन की दिशा में एक और प्रभावी कदम

भोपाल (नप्र)। एम.पी. ट्रांसको (मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी) ने अपने कार्यालयीन प्रक्रियाओं में नई तकनीकों के समावेश को आगे बढ़ाते हुए डिजिटाइजेशन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जानकारी दी कि मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यों के बिलों का भुगतान, जो पूर्व में भौतिक मापन पुस्तिका में मैन्युअल प्रविष्टि के बाद होता था, अब वह डिजिटल एम.बी. के माध्यम से ही होगा। एम.पी. ट्रांसको के विभिन्न विभागों में इसका उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है।

मंत्री श्री तोमर ने बताया कि अब संपूर्ण मध्यप्रदेश में एम.पी. ट्रांसको के कार्यालयों में शत प्रतिशत पारदर्शिता के साथ वेंडर, ठेकेदारों आदि के बिल डिजिटल एम.बी. के माध्यम से भुगतान किये जा रहे हैं। इससे न केवल भुगतान की प्रक्रिया आसान हुई है बल्कि वेंडर, कॉन्ट्रेक्टर आदि भी अपने बिलों की करंट स्टेट्स से अवगत रहते हैं। साथ ही उन्हें निर्धारित समय पर भुगतान प्राप्त भी हो रहा है।

इन हाउस विकसित किया

एम.पी. ट्रांसको के अधीक्षण अभियंता श्री अजय पांडे ने बताया कि इस डिजिटल एम.बी. को कंपनी की आई.टी. एवं ई.आर.पी. सेल ने कंपनी के वित्तीय विभाग से समन्वय बनाकर इनहाउस विकसित किया है। डिजिटल एम.बी. में वेंडर और कॉन्ट्रेक्टर की उनके द्वारा किए गए कार्यों के पार्ट पेमेंट का नियमानुसार भुगतान करने की भी सुविधा दी गई है। सॉफ्टवेयर से किए गए कार्य, उपयोग हुआ मटेरियल और शेष कार्य तथा मटेरियल की गणना कर भुगतान की राशि निकल आती है।

क्या है डिजिटल एम.बी.

डिजिटल एम.बी. एक डिजिटल मापन पुस्तिका है। यह सरकारी कार्यालयों में बाहरी एजेंसी द्वारा किए गए कार्यों, सप्लाई किये गए मटेरियल के बदले भुगतान प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। यह किए गए कार्य की वास्तविक माप या गिनती का मूल अभिलेख कहलाता है।

आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को मिलेगा 55 प्रतिशत भत्ता

एमपी के साढ़े सात लाख कर्मचारी, अधिकारी फिर 5 प्रतिशत कम महंगाई भत्ता पाएंगे

भोपाल (नप्र)। एमपी में पदस्थ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और राज्य में प्रतिनियुक्त पर सेवा देने वाले कर्मचारियों को अब 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके बाद एमपी के कर्मचारी और अधिकारी एक बार फिर महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों से 5 प्रतिशत पीछे हो गए हैं। पिछले माह यह अंतर तीन प्रतिशत था जो इस माह केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए 2 प्रतिशत भत्ते के चलते बढ़कर पांच प्रतिशत हो गया है।

एमपी के कर्मचारियों और अधिकारियों को पहले ही जुलाई 2024 से तीन प्रतिशत कम भत्ता मिल रहा था और अब केंद्र के कर्मचारियों को जनवरी 2025 से मिलने वाले 2 प्रतिशत भत्ते के कारण वे और पीछे रह गए हैं। राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा पिछले सप्ताह जारी आदेश में सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, राजस्व मंडल ग्वालियर, सभी संभागायुक्त और कलेक्टरों को दिए निर्देश में कहा है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक जनवरी 2025 से पुनरीक्षित दर पर महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा 2 अप्रेल 2025 को जारी आदेश में एक जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता मंजूर किया गया है। इसके बाद केंद्र के कर्मचारियों और अधिकारियों को अब एक जनवरी 2025 से मूल वेतन के 53 प्रतिशत के बजाय दो प्रतिशत अधिक यानी 55 प्रतिशत प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसी के आधार पर राज्य सरकार के वित्त विभाग ने भी 17 अप्रैल को केंद्र के कर्मचारियों और अधिकारियों को एक जनवरी 2025 से 53 की बजाय 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार यह भुगतान नकद करेगी।

मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी का कहना है कि एमपी के कर्मचारियों को अभी 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है जबकि केंद्र के कर्मचारी 55 प्रतिशत भत्ता पा रहे हैं। इस तरह राज्य के कर्मचारी 5 प्रतिशत पीछे हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से कम मिल रहा था और अब केंद्र द्वारा एक जनवरी 2025 से यह राशि दो प्रतिशत बढ़ा दी, तो राज्य का कर्मचारी अधिकारी पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता कम पा रहा है। पहले एमपी के कर्मचारियों को 46 प्रतिशत ही महंगाई भत्ता मिल रहा था जिसे मार्च 2025 में राज्य सरकार ने चार प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया था।

ईडी कोर्ट में सौरभ शर्मा की जमानत पर सुनवाई पूरी

सौरभ के वकील का तर्क ईडी के तमाम आरोप मनगढ़ंत, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

भोपाल (नप्र)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कोर्ट में आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा की ओर से एडवोकेट दीपेश जोशी और सौरभ के सहयोगी शरद जायसवाल की ओर से अधिवक्ता रजनीश बरैया ने सोमवार को जमानत याचिका दायर की। विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत में इस जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सौरभ शर्मा की मां और ईडी की टीम अदालत में मौजूद रहीं।

ईडी के वकील विक्रम सिंह ने सौरभ और शरद के कृत्य को गंभीर बताते हुए उनकी जमानत का विरोध किया। वहीं, सौरभ के वकील दीपेश जोशी ने ईडी की कार्रवाई को काल्पनिक बताते हुए सभी आरोपों को गलत बताया और जमानत दिए जाने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।

मां और पत्नी को इसी कोर्ट से मिल चुकी है जमानत

9 अप्रैल को इसी कोर्ट से सौरभ की मां उमा शर्मा, पत्नी दिव्या शर्मा, जीजा विनय आसवानी और जबलपुर निवासी साले रोहित तिवारी को जमानत मिल गई थी। 18वें अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत से 10 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई थी। वहीं, जमानत नहीं मिलने की हालत में सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी शरद और चेतन की पेशी 5 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी।

ईडी ने 8 अप्रैल को पेश किया था चालान

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भोपाल ने आरटीओ के करोड़पति पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा उसके सहयोगियों शरद जायसवाल, चेतन सिंह गौर के खिलाफ 8 अप्रैल मंगलवार को कोर्ट में चालान पेश किया था। इसमें इनोवा कार में मिला 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश सौरभ का ही बताया गया है।

हेल्थ डिपार्टमेंट अपनाएगा ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन प्रोसेस

स्कूल शिक्षा विभाग की तर्ज पर ई-एचआरएमएस माड्यूल पर आवेदन कर सकेंगे कर्मचारी

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में नई तबादला नीति जारी होने के पहले अब लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग खुद के द्वारा तैयार कराए गए माड्यूल पर आवेदन बुलाने और आदेश जारी करने की प्रक्रिया अपनाएगा। इसका फायदा प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में अलग-अलग सेक्टर में काम कर रहे 46 हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग पहले ही तबादलों को लेकर ऑनलाइन माड्यूल सिस्टम पर काम कर रहा है।

उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बुधवार को मंत्रालय में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल (ई-एचआरएमएस) की तैयारियों का रिव्यू किया। इस बैठक में उन्हें माड्यूल की व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मॉड्यूल राज्य सरकार की तबादला नीति के सिद्धांतों एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि तबादला नीति का पूरी तरह पालन करते हुए इस प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए। उन्होंने साफ किया कि मॉड्यूल में सभी आवश्यक मापदंडों का समावेश ऐसे किया जाए कि किसी भी कर्मचारी को अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर अगले कुछ दिनों में प्रदेश में कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लागू प्रतिबंध हटाया जाने वाला है। इसलिए इसी समयावधि को ध्यान में रखते हुए ई-एचआरएमएस मॉड्यूल की अंतिम टेस्टिंग पूर्ण कर ली जाए, ताकि प्रतिबंध हटते ही तबादला प्रक्रिया बिना किसी बाधा, सुगमता और पारदर्शिता के साथ संचालित की जा सके।

अगले हफ्ते कैबिनेट दे सकती है तबादला नीति को मंजूरी- मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कहा है कि अगली कैबिनेट बैठक में तबादला नीति का ड्राफ्ट पेश किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पेश किए जाने वाले तबादला नीति के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद एक मई से 31 मई तक राज्य स्तर पर तबादले किए जा सकेंगे।

एक्सीडेंट में घायल महिला की मौत

पति की दो दिन पहले गई थी जान, दोनों एक बाइक पर सवार थे

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कोलार इलाके में रहने वाली महिला की इलाज के दौरान बुधवार सुबह हमीदिया अस्पताल में मौत हो गई। सोमवार को पति के साथ बाइक पर सवार होकर ड्यूटी जा रही थी। तभी उनकी बाइक एक ट्रैक्टर से टकरा गई थी। इस हादसे में घायल महिला के पति की सोमवार शाम को इलाज के दौरान जान चली गई थी। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक सोनू बाल्मीक (39) पति कैलाश बाल्मीक कजलीखेड़ा में रहती थी। वह और उसका पति कोलार के एक अस्पताल में सफाई कार्य करते थे। दोनों होंडा शाइन बाइक पर सवार होकर सोमवार को ड्यूटी पर जा रहे थे। मदर टेरेसा स्कूल के पास उनकी बाइक एक ट्रैक्टर से टकरा गई।

हादसे में घायल पति और पत्नी को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार की शाम को इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। दो दिन बाद बुधवार की सुबह पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। दोनों के दो बच्चे एक लड़का और एक लड़की है। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस का कहना है कि हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है।

मिनी ट्रक की टक्कर से महिला की मौत

छोला मंदिर पुलिस के मुताबिक रजिया खान (25) कम्मू का बाग थाना ऐशबाग में रहती थी और गृहणी थी। मंगलवार रात वह परिवार वालों के साथ ईंटखेड़ी स्थित एक शादी समारोह में जाने के लिए निकली थी। पूरा परिवार ऑटो में सवार था। रात करीब पौने दस बजे ऑटो छोला मंदिर स्थित सीमेंट गोदाम के पास पहुंचा, तभी ईंट ढोने वाले एक मिनी ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। रजिया ऑटो में किनारे बैठी थी, इसलिए उसे सबसे ज्यादा चोट आई थी। उसे इलाज के लिए पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने टक्कर मारने वाले ट्रक को जब्त कर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

बीज निगम के एमडी नहीं दे रहे कर्मचारियों के क्लेम

41 डिग्री तापमान में रिटायर कर्मचारियों ने दिया धरना, भुगतान के लिए सड़कों पर उतरेंगे

भोपाल (नप्र)। एमपी बीज निगम के कर्मचारियों को एक ओर पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर बीज निगम प्रबंधन छह साल से ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण और अन्य क्लेम का भुगतान नहीं कर रहा है। इससे बीज निगम से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को परिवार के भरण पोषण की दिक्कतों से दो-चार होना पड़ रहा है। ऐसे में अपनी मांगों की पूर्ति के लिए बीज निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन 41 डिग्री तापमान में तीन दिन से जारी है।

सेवानिवृत अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने बीज निगम के सेवानिवृत अधिकारियों-कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण एवं अन्य क्लेम की मांग की है, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इन सबने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव कृषि और किसान कल्याण विभाग को ज्ञापन सौंपा। बीज निगम के एमडी द्वारा इस प्रदर्शन को देखते हुए बिजली कनेक्शन काटा गया जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है।

फेडरेशन के महासचिव अरुण वर्मा ने बताया कि सेवानिवृत कर्मचारियों का ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण एवं अन्य क्लेम का भुगतान मूलभूत अधिकार है। बीज निगम प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019 से अभी तक सेवानिवृत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण अन्य क्लेम का भुगतान नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है।

कर्मचारियों का कहना है कि हमें पेंशन नहीं मिलने के कारण ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण एवं अन्य क्लेम ही परिवार जनों के भरण पोषण का मुख्य आधार है। यदि भुगतान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही सड़कों पर उतरेंगे और प्रबंध संचालक के निवास पर जाकर नींद हराम आंदोलन कर प्रबंधन का पुतला भी जलाएंगे।

प्रदर्शन सभा को अरुण वर्मा, ओपी सोनी, पीसी जैन राजेश वर्मा, एसएस तिवारी सहित अन्य कर्मचारी नेताओं ने संबोधित किया। इन मांगों को लेकर 41 डिग्री तापमान में निगम मुख्यालय में तीसरे दिन धरना प्रदर्शन जारी रहा।

संपादकीय

'बिहारी फर्स्ट' के सियासी मायने

देश में वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ मुसलमानों के विरोध, कश्मीर में आतंकी हमले और संवैधानिक संस्थाओं के बीच हो रहे आरोप-प्रत्यारोप के बीच बिहार की राजनीति कुछ अलग रास्ते पर चल रही है। राज्य में छह माह बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन महागठबंधन से ज्यादा एनडीए में घमासान नजर आ रहा है। यह स्थिति तब है कि जब राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की जीत की संभावना ज्यादा है। एनडीए की बाजी के मुख्य खिलाड़ी राष्ट्रीय जनता पार्टी के (रा) के मुखिया एवं केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं। चिराग ने विस चुनाव से पहले नया नारा 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' नारा देकर एनडीए के सहयोगी दलों में खलबली मचा दी है। सभी पार्टियां पासवान के इस दांव को बूझने की कोशिश कर रहीं हैं कि चिराग की असली महत्वाकांक्षा क्या है? क्या वो सीएम पद के दावेदार हैं? अगर ऐसा है तो नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के वादों का क्या हुआ? या फिर यह केवल दबाव की राजनीति है? गौरतलब है कि चिराग पासवान ने हाल ही में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मेरा ध्यान बिहार पर है, बिहार मुझे बुला रहा है।' उनकी इस टिप्पणी को भाजपा और जनता दल (यू) के खेमों में सीट बंटवारे के लिए दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल चिराग की पार्टी, एलजेपी (रा) विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। चिराग ने अपने 'बिहार फर्स्ट' के नजरिए को रेखांकित करते हुए कहा था कि मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं। बिहार से बाहर निकलकर बिहारी हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं।' उन्होंने अपनी पार्टी की रणनीति में महिलाओं और युवाओं (महिला और युवा फॉर्मूला) को विशेष महत्व देने की बात भी कही। हालांकि, चिराग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी नजर 2030 के चुनावों पर हो सकती है। एक एलजेपी (रा) नेता ने बताया कि चिराग की हालिया बिहार-केंद्रित टिप्पणियाँ उनकी पार्टी के लिए सम्मानजनक सीट हिस्सेदारी हासिल करने की रणनीति का हिस्सा हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ने बिहार में सभी पांच सीटें जीतकर शानदार वापसी की थी, जबकि एनडीए के बड़े सहयोगी भाजपा और जद (यू) ने क्रमशः 12-12 सीटें जीती थीं। भाजपा और जेडीयू नेता भी चिराग के बयानों को सीटों के मोलभाव के रूप में देख रहे हैं। इसमें शक नहीं कि कोई भी पार्टी सीटों का मोलभाव तभी कर पाती है, जब उसका वोट शेयर कम से कम 15 प्रतिशत हो। चिराग की पार्टी ने यह खेल 2020 के विस चुनाव में किया था, जब उनकी पार्टी जेडी यू के लिए वोट कटवा साबित हुई थी। परिणामस्वरूप जेडी यू चुनाव में नंबर दो पार्टी बनकर रह गई थी। तब माना गया था कि इसके पीछे असली खेल भाजपा का था, जो नीतीश को उनकी हैसियत दिखाना चाहती थी। इसीलिए पहले चिराग को एनडीए से अलग करवाया गया और उनके जरिए नीतीश पर हमले करवाए गए हैं। हालांकि इस बार नीतीश एनडीए से अलग होकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए इस रणनीति पर काम कर रहे हों। उधर बिहार के उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने चिराग का नाम लिए बिना कहा कि कोई अभिनेता बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। केवल जमीनी नेता ही इस पद के हकदार हैं। बहरहाल राजनीतिक प्रेक्षकों की नजरें बिहार में चिराग की अगली चालों पर है।

खूबसूरत कश्मीर की खूनी दास्तान

नजरिया

नृपेन्द्र अभिषेक नृप

लेखक स्तंभकार हैं।

कश्मीर जहां कभी सिर्फ वादियों की खामोशी और झीलों की शांति बसी थी, 1980 के दशक के बाद आतंकवाद की चपेट में आ गया। इस कालखंड में पाकिस्तान प्रायोजित उग्रवादियों ने घाटी में कट्टरपंथी विचारधारा का बीज बोना शुरू किया। धार्मिक उन्माद और अलगाववादी सोच को हवा दी गई, जिससे कश्मीर के युवाओं को यह भ्रमित कर भड़काया गया कि भारत उनका दमनकारी है और पाकिस्तान उनका संरक्षक। इस भ्रामक प्रचार के प्रभाव में आकर अनेक युवा बंदूकें उठाने लगे और 'जिहाद' के नाम पर हिंसा फैलाने लगे। यह सब कुछ उस ज़मीन पर हुआ जो कभी सूफियों और संतों की सांझी विरासत की मिसाल हुआ करती थी।

1990 के दशक में आतंकवाद ने विकराल रूप ले लिया। सबसे भयावह दृश्य तब देखने को मिला जब सैकड़ों कश्मीरी पंडितों को जान बचाकर घाटी से पलायन करना पड़ा। यह पलायन केवल एक सांस्कृतिक समूह का विस्थापन नहीं था, बल्कि कश्मीर की साझी संस्कृति पर एक करारा आघात था। उस दौर में मुठभेड़ें, बम धमाकों और अपहरणों की घटनाएँ आम हो गई थीं। भारत सरकार और सुरक्षाबलों ने भरपूर प्रयास किए, मगर स्थायी समाधान बना रहा, कभी राजनीतिक नेतृत्व के अभाव में, तो कभी स्थानीय समर्थन के न मिलने के कारण।

अनुच्छेद 370 के निरसन का प्रभाव

5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। जम्मू-कश्मीर से उसका विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बाँट दिया गया। सरकार का तर्क था कि यह कदम आतंकवाद, अलगाववाद और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की दिशा में निर्णायक होगा। प्रारंभ में कठोर सुरक्षा उपाय किए गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया, नेताओं को नजरबंद किया गया और जनसभाओं पर रोक लगाई गई। घाटी में कुछ समय के लिए अपेक्षाकृत शांति बनी रही।

हालांकि, जैसे-जैसे समय बीता और जनजीवन सामान्य होता गया, छिटपुट आतंकी हमलों ने फिर सिर उठाना शुरू कर दिया। यह स्पष्ट हो गया कि केवल संवैधानिक बदलाव काफी नहीं हैं आतंकवाद की जड़ें गहरी हैं और समाधान केवल सुरक्षा के सहारे संभव नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक स्तर पर भी लड़ाई लड़नी होगी। कश्मीर को फिर से अपने मूल रूप में लाने के लिए बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है।

आतंकवाद के पीछे के मुख्य कारण

1. पाकिस्तान का हस्तक्षेप: अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को घेरने की कोशिश- पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को दशकों से अपनी विदेश नीति का केन्द्रीय बिंदु बना रखा है। वह समय-समय पर संयुक्त राष्ट्र, इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) और अन्य वैश्विक मंचों पर इसे उठाकर भारत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने का प्रयास करता है। हालांकि अधिकांश देश अब कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की कोशिशें थमी नहीं हैं। इससे अधिक चिंताजनक बात यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देती है। वह आतंकी संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिज्बुल मुजाहिदीन को प्रशिक्षण, हथियार और फंडिंग उपलब्ध कराकर भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देती है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कश्मीर के युवाओं को बरगलाने की रणनीति अब और अधिक परिष्कृत हो गई है।

2. स्थानीय असंतोष: कट्टरपंथ की ओर धकेलता मनोविज्ञान- कश्मीर में वर्षों से चली आ रही सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ युवाओं को आतंक की ओर धकेलने में सहायक रही हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास की असमानता और प्रशासन के प्रति अविश्वास ये सभी कारक युवाओं को असंतोष से भर देते हैं। जब राज्य या केंद्र सरकार की योजनाएं ज़मीन पर लागू नहीं होतीं या उनका लाभ वास्तविक पात्रों तक नहीं पहुँचता, तब समाज में निराशा का वातावरण पनपता है। इस परिस्थिति में जब आतंकी संगठन उन्हें 'सम्मान', 'उद्देश्य' और 'बदलाव' के झूठे सपने दिखाते हैं, तो कई युवा इस भ्रम में आ जाते हैं। यह कट्टरपंथ धीरे-धीरे समाज में हिंसा और विभाजन का बीज बोता है।

3. प्राकृतिक एवं भौगोलिक चुनौती: दुर्गम सीमाओं की जटिलता- कश्मीर की भौगोलिक बनावट भारत के सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। बर्फीली चोटियाँ, घने जंगल, और ऊँचाई पर बसी बस्तियाँ सीमापार निगरानी को कठिन बना देती हैं। LOC (लाइन ऑफ कंट्रोल) पर स्थित गाँवों के रास्ते से कई बार आतंकी आसानी से घुसपैठ कर जाते हैं। मौसम की प्रतिकूलता और संचार की बाधाएँ इस निगरानी को और भी जटिल बना देती हैं। हालांकि आधुनिक तकनीक जैसे सैटेलाइट सर्वे, ड्रोन और मोशन डिटेक्शन उपकरण का प्रयोग हो रहा है, फिर भी हर प्रवेश मार्ग पर सख्त नियंत्रण कायम करना एक सतत और कठिन प्रक्रिया बनी हुई है।

4. स्थानीय समर्थन की कमी: सुरक्षा तंत्र की कमजोर कड़ी- किसी भी आतंकवाद-विरोधी अभियान की सफलता जनता के सहयोग पर निर्भर करती है। कश्मीर में अनेक बार यह देखा गया है कि जब सुरक्षा बल किसी अभियान को अंजाम देते हैं, तो कुछ स्थानीय लोग प्रतिरोध करते हैं या पत्थरबाज़ी करते हैं। इससे न केवल अभियान में बाधा आती है, बल्कि सुरक्षा बलों को अनावश्यक हिंसा का सहारा लेना पड़ता है, जिससे और अधिक असंतोष जन्म लेता है। इस चक्र को तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए संवाद, जागरूकता और प्रशासनिक विश्वास बहाली की आवश्यकता है। यदि स्थानीय समाज आतंक के विरुद्ध स्पष्ट रुख अपनाए और सुरक्षा एजेंसियों को सूचनाएँ दे, तो आतंकी नेटवर्क को तोड़ना संभव हो सकेगा।

5. पहलगाम हमला और इसके संकेत: सॉफ्ट टारगेट्स पर बढ़ता खतरा- पहलगाम, कश्मीर घाटी का एक सुंदर, शांत और विश्वविख्यात पर्यटन स्थल है। वर्षों से यहाँ लाखों पर्यटक आते रहे हैं, जिससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ, बल्कि घाटी के प्रति देश और विश्व में सकारात्मक धारणा बनी। हालिया आतंकी हमला न केवल निर्दोष नागरिकों की जान लेने का प्रयास था, बल्कि इसकी गूढ़ रणनीति भी स्पष्ट है, कश्मीर को असुरक्षित दर्शाना, भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करना, और स्थानीय पर्यटन एवं रोजगार को ध्वस्त करना। यह हमला यह भी दर्शाता है कि आतंकवादी अब सैन्य ठिकानों या बड़े सुरक्षा प्रतिष्ठानों की बजाय 'सॉफ्ट टारगेट्स' जैसे पर्यटक, गैर-कश्मीरी मज़दूर और छोटे व्यापारी को निशाना बना रहे हैं। इसका उद्देश्य डर और भ्रम का वातावरण बनाना है, ताकि विकास की गति रुके और कश्मीर फिर से हिंसा की गिरफ्त में आ जाए।

कैसे ख़त्म होगा आतंकवाद?

कश्मीर की समस्या केवल आतंकवाद और अलगाववाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समग्र सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक चुनौती है, जिसका समाधान केवल सैन्य बल या कठोर नीतियों से संभव नहीं। इसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक समावेश, आर्थिक अवसर, राजनीतिक भागीदारी और सांस्कृतिक पुनर्जीवन शामिल हो।

1. सुरक्षा ढांचे का आधुनिकीकरण: नवाचार की ज़रूरत- कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा केवल हथियारबंद बलों की उपस्थिति तक सीमित नहीं रह सकती। बदलते समय और आतंकवाद के नए स्वरूप को देखते हुए, हमें निगरानी और प्रतिक्रिया की प्रणाली को आधुनिक बनाना होगा। ड्रोन तकनीक, सैटेलाइट इमेजिंग, थर्मल स्कैनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली–इन सभी का समुचित उपयोग आतंकवाद की शुरुआती पहचान और रोकथाम में सहायक हो सकता है। साथ ही, साइबर इंटेलिजेंस और डार्क वेब पर निगरानी जैसे उपाय आतंकी फंडिंग और भर्ती नेटवर्क को निष्क्रिय कर सकते हैं।

2. युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ना: शिक्षा और रोजगार की चाबी- कश्मीर के युवाओं के हाथ में जब बंदूक की जगह किताब और कलम आएगी, तभी घाटी में स्थायी शांति संभव होगी। आज की आवश्यकता है कि युवाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया जाए। इसके लिए स्टार्टअप योजनाएं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण, कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प को बढ़ावा, और डिजिटल सेवाओं से जुड़ी नौकरियाँ सृजित की जानी चाहिए। इससे न केवल युवाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, बल्कि वे कट्टरपंथ की राह से भी दूर रहेंगे।

3. संवाद और सांस्कृतिक पुनर्जागरण: 'कश्मीरियत' की पुर्नस्थापना- कश्मीर की आत्मा उसकी 'कश्मीरियत' में निहित है–जो सहिष्णुता, विविधता और मेल-मिलाप की संस्कृति को दर्शाती है। बीते दशकों में यह भावना विस्मृत हो गई है। उसे पुनर्जीवित करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार और नागरिक संगठनों को स्थानीय पर्वों, सूफी संगीत, कला, हस्तशिल्प मेलों, कवि सम्मेलनों और सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करना चाहिए। इससे समाज में मेल-जोल बढ़ेगा, युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने का अवसर मिलेगा और आतंकवाद की कट्टर विचारधारा को चुनौती मिलेगी।

4. पाकिस्तान को बेनकाब करना: वैश्विक स्तर पर सशक्त रणनीति- भारत को पाकिस्तान की दोहरी नीति–जहां वह एक ओर शांति की बात करता है और दूसरी ओर आतंकवाद को समर्थन देता है–को वैश्विक मंचों पर लगातार उजागर करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र, G-20, SCO जैसे मंचों पर पाकिस्तान की भूमिका को प्रमाण सहित सामने लाना और FATF जैसे संस्थानों में उसकी निगरानी बनाए रखना आवश्यक है। इसके साथ ही, भारत को सीमा प्रबंधन में तकनीकी दक्षता और राजनयिक संतुलन बनाए रखना होगा ताकि क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे।

5. निष्पक्ष शासन और पारदर्शी प्रशासन: विश्वास की बहाली- कश्मीर में दशकों से चली आ रही प्रशासनिक उदासीनता और भ्रष्टाचार ने स्थानीय जनता के विश्वास को गहरा आघात पहुँचाया है। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए ई-गवर्नेंस को व्यापक स्तर पर लागू करना चाहिए। लाभार्थी योजनाओं की निगरानी, ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र, ग्राम स्तर पर पंचायत सशक्तिकरण और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया जैसे उपाय प्रशासनिक प्रणाली को जनता के प्रति जवाबदेह बनाएँगे। जब आम नागरिक यह देखेगा कि शासन निष्पक्ष और संवेदनशील है, तो उसका विश्वास धीरे-धीरे लौटेगा।

6. स्थानीय नेतृत्व: विकास और संवेदनशीलता का समन्वय- कश्मीर के नेताओं को अब अपनी भूमिका आत्ममंथन के साथ पुनर्परिभाषित करनी चाहिए। वे यदि अपने राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर शांति, समावेश और विकास के लिए कार्य करें, तो समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा। ज़मीनी स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाना, युवाओं से संवाद, विकास योजनाओं की निगरानी और सांप्रदायिक सौहार्द्र को बढ़ावा देना–इन कार्यों में स्थानीय नेताओं को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

7. मीडिया और शिक्षा: नई पीढ़ी के मानस का निर्माण- मीडिया को चाहिए कि वह सनसनी फैलाने की बजाय समाधानात्मक पत्रकारिता को बढ़ावा दे। घाटी के सकारात्मक प्रयासों, शांति की कोशिशों और युवाओं की उपलब्धियों को सामने लाना मीडिया की ज़िम्मेदारी है। वहीं शिक्षा क्षेत्र में समावेशी दृष्टिकोण, आलोचनात्मक सोच, सहिष्णुता, और भारतीयता के व्यापक भाव को पाठ्यक्रमों में समाहित करना होगा। इससे भावी पीढ़ी में कट्टरता के विरुद्ध बौद्धिक ढाल विकसित होगी।

8. आम नागरिकों की सहभागिता: सामाजिक सुरक्षा का आधार- आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए समाज की साझेदारी अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय निवासी यदि संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी समय पर दें, समाज में भाईचारे का वातावरण बनाए रखें और पीड़ितों के साथ खड़े हों, तो आतंकवादी नेटवर्क कमजोर होगा। सामाजिक संस्थाएँ, महिला समूह, युवा मंडल और धार्मिक नेताओं को भी इस लड़ाई में भागीदार बनाना चाहिए।

9. आशा की ओर बढ़ते कदम: एक संभावनाशील भविष्य- पिछले कुछ वर्षों में घाटी में बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार देखने को मिला है। बेहतर सड़कें, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली की उपलब्धता, और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। स्कूली नामांकन में वृद्धि, खासकर बालिकाओं की भागीदारी, कश्मीर में बदलते सामाजिक परिदृश्य की संकेतक है। पर्यटक एक बार फिर घाटी की वादियों में लौटे हैं, जो कि विश्वास और शांति का प्रतीक है।

यदि बहुस्तरीय और दीर्घकालिक रणनीतियों को लागू किया जाए, स्थानीय जनता का विश्वास जीता जाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की साजिशों को विफल किया जाए, तो आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंका जा सकता है। कश्मीर को केवल सुरक्षा से नहीं, बल्कि विश्वास, विकास और संवाद से जीतना होगा। यही भारत की असली विजय होगी। यदि यही प्रवृत्ति जारी रही और उपर्युक्त सुधारों को नीतिगत समर्थन मिला, तो कश्मीर आने वाले वर्षों में केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि शांति, सौहार्द और साझेदारी का प्रतीक बन सकता है, जहाँ बंदूकें नहीं, बल्कि बांसुरी की धुनें सुनाई देंगी और जहाँ डर नहीं, बल्कि उम्मीदें घर बनाएंगी।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर विशेष

सशक्त पंचायतों से ही बनेगा विकसित राष्ट्र

रमेश सर्राफ धमोरा

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

भारत गांवों का देश है। यहां की बहुसंख्यक आबादी आज भी गांवों में रहती है। भारत के गांव ही देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक देश कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। गांव में सुशासन स्थापित करने के लिए ही ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी। हमारे देश के नेताओं को ग्रामीण पृष्ठभूमि का पूरा ज्ञान था। इसलिए उन्होंने गांव के महत्व को समझकर ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी। उनको पता था कि जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक देश मजबूत नहीं होगा। गांव को मजबूत करने के लिए यहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था।

आजादी के समय भारत के गांव बहुत पिछड़े हुए थे। देश के अधिकांश गांवों में मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं था। मगर आज गांवों की व्यवस्था भी बहुत कुछ बदल गई है। आज देश के बहुत से गांव में शहरों की भांति सुविधा देखने को मिल रही है। लेकिन आज भी देश में हजारों ऐसे गांव है जहां पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई है। जब तक सरकार देश के सभी गांव में समान रूप से सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाएगी तब तक देश विकास की दौड़ में पूरी गति से शामिल नहीं हो पाएगा। हम आज पंचायती राज दिवस मना रहे हैं। हमारे देश में 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। 1993 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह एक संवैधानिक इकाई के रूप में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का प्रतीक है। पंचायती राज प्रणाली भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सत्ता और संसाधनों का विकेंद्रीकरण करना और सहभागी लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। पंचायती राज प्रणाली जमीनी स्तर पर लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने और उनके विकास का स्वामित्व लेने में सक्षम बनाती है, जो स्व-शासन और जवाबदेही को बढ़ावा देने में मदद करती है।

भारत गांवों का देश माना जाता है और गांव के विकास में पंचायतों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चूंकि ग्राम पंचायतों के पंच व सरपंच सीधे ग्रामीणों द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों से सीधा संपर्क रहता है। ग्रामवासी भी अपनी समस्याएं सीधे पंचायत तक पहुंचा सकतें है। मगर ग्राम पंचायतों की स्थापना के इतने वर्षों के बाद भी अभी तक ग्राम पंचायतें वास्तविक रूप में सशक्त नहीं हो पाई है। ग्राम पंचायतें पूरी तरह राज्य सरकारों पर निर्भर है। कहने को तो ग्राम पंचायतों को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं। मगर आज तक भी अपने अधिकारों का ग्राम पंचायतें प्रयोग नहीं कर पाती है। आज भी देश की अधिकांश ग्राम पंचायतों में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी प्रभावी रहते हैं।

ग्राम पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था लागू होने के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं पंच, सरपंच निर्वाचित होकर आती है। उनमें से कई महिलाएं तो वास्तव में बहुत अधिक पढ़ी लिखी होने के कारण पूरी जानकारी रखती है। इस कारण वह अपने अधिकारों का पूरा प्रयोग कर लेती है। मगर अधिकांशतः आरक्षण के कारण गांवो में प्रभावी नेता अपने परिवार की किसी महिला को पंच, सरपंच बनवा देते हैं। फिर उनके स्थान पर खुद नेतागिरी करते हैं। वहां की निर्वाचित महिलाएं मात्र कागजी जनप्रतिनिधि बन कर रह जाती है। बहुत से स्थानों पर तो महिला सरपंचों के हस्ताक्षर भी उनके स्थान पर काम करने वाले उनके परिजनों द्वारा ही कर दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में पंचायत राज व्यवस्था के मजबूत होने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सरकार बार-बार परिपत्र जारी कर सरपंच के प्रतिनिधियों को पंचायतों के कार्यों में हस्तक्षेप करने से मना करती है। मगर धरातल में सरकार के परिपत्र मात्र कागजी बन कर रह जाते हैं।

देश में आज चाहे ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो। जहां भी महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर आती है। उनके स्थान पर उनके परिजन ही कार्य करते देखे जा सकते हैं। सभी प्रदेशों की राज्य सरकारों को कड़ाई से इस पर रोक लगाई जानी चाहिए ताकि महिलाओं को भी अपने पद पर काम करने का मौका मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखने में आता है कि निर्वाचित पंच, सरपंच पंचायतों की बैठक में घूंघट निकाल कर बैठते हैं। क्योंकि वहां उनके ससुराल वाले बड़े परिजन की बैठे रहते हैं। आज देश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर रहा है। महिलाएं हर क्षेत्र में अपने काम से धूम मचा रही है। अब तो सेना को भी महिलाओं के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों का घूंघट निकाल कर बैठना सभ्य समाज के लिए किसी दुखद घटना से कम नहीं है। सरकार को ऐसी घटनाओं पर भी सख्ती बरतनी चाहिये।

पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं का जीवन बहुत प्रभावित हुआ है। सही मायने में पंचायती राज ने महिलाओं को समाज का एक विशेष सदस्य बना दिया है। लाखों महिलाऐं सार्वजनिक जीवन में आयी हैं। लेकिन अधिकतर निर्वाचित महिलाओं को निर्वाचक सदस्य होने के विषय में पूर्ण जानकारी भी नहीं है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी के कारण वह प्रभावी नहीं हो पाती हैं। तथा उन्हे यह भी ज्ञान नहीं होता है कि वह एक कुशल प्रशासक भी हो सकती हैं।

घूंघट में रहना लोकतंत्र और औरत जाति के लिए एक चुनौती है। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है लेकिन औरतो के प्रति लोगों की सोच अभी तक नहीं बदली है। राजनीति घूंघट में रह कर नहीं हो सकती। इसके लिए बेबाक होना पड़ता है। जब औरतें किसी कार्यक्रम में मंच पर घूंघट निकाल कर बैठेंगी तो वहां के हालात बड़े अजीबोगरीब हो जाते हैं। औरतों को अपने से कमतर मानने की सोच के चलते ही उन के चेहरे से परदा नहीं हट पा रहा है। लोकतंत्र की सबसे छोटी संसद पंचायती राज में हालांकि महिलाएं 50 फीसदी सीटों पर काबिज हैं। लेकिन इन महिला जनप्रतिनिधियों में से कई पढ़ी-लिखी होने के बाद भी ग्राम पंचायत की मिटिंगों में घूंघट में बैठी रहकर जुबान ही नहीं खोलतीं है।

क्या ऐसी स्थिति के लिए ही पंचायत राज को मजबूती देने का निर्णय किया गया था। क्या इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने के बाद भी हमारे देश की महिला जनप्रतिनिधियो को घूंघट की ओट में ही जीने को विवश होना पड़ेगा। यह एक बड़ा सवाल है जिसे ना सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियो को गंभीरता से लेना पड़ेगा बल्कि राजनेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों को भी सरपंच पतियो के बढ़ते हस्तक्षेप पर प्रभावी अंकुश लगाना होगा। औरतों के सिर से घूंघट हटाने के लिए लड़कियों के मातापिता को आगे आना होगा। उन्हें अपनी बेटियों की शादी उसी परिवार में करनी चाहिए जहां घूंघट का बंधन नहीं हो। घूंघट में रह कर औरतें अपनी जिंदगी के तानेबाने को कैसे बुन सकती हैं? घूंघट में रह कर राजनीति या समाजसेवा नहीं की जा सकती।

आज के समय में ग्राम पंचायते पैसे कमाने का जरिया बन गई है। पंचायत चुनाव में बड़ी मात्रा में पैसे खर्च होते हैं। चुनाव जीतने के बाद निर्वाचित सरपंच द्वारा जनसेवा के बजाय पैसे कमाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत के सामाजिक सरोकार के कामों को भूल कर निर्माण कामों में व्यस्त हो जाते हैं। अपनी पंचायत में अधिक से अधिक निर्माण कार्य स्वीकृत करवाने के लिए सरपंच विधायकों, सांसदों के चक्कर काटते रहते हैं। जिस कारण वह उनके दबाव में काम करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को सही मायने में सशक्त बनाने के लिए सरकार को सभी प्रकार के निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों से हटाकर संबंधित विभागों से करवाया जाना चाहिए ताकि सरपंच जनता से जुड़ कर उनकी समस्याओं का सही मायने में समाधान करवा सकें।

प्रभावी प्रतिरोधात्मक रणनीति आवश्यक

पहलगाम हमला

अमित राव पवार

लेखक स्तंभकार हैं।

भारत, जहाँ पश्चिम बंगाल सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस रहा था, उसीदौरान 22 अप्रैल 2025, मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ आतंकवादी हमला एक और दर्दनाक अध्याय बन गया। यह हमला किसी राज्य,भाषा या जाति पर नहीं, बल्कि सीधे धर्म के नाम पर किया गया हमला था। आतंकवादियों ने पर्यटकों से उनके नाम पूछे और हिंदू नाम सुनते ही उन्हें गोली मार दी।

इन मासूमों का अपराध क्या था? केवल यही कि वे हिंदू थे? इस प्रकार की मानसिकता केवल हमारे वर्तमान की नहीं,इतिहास की भी एक गूंज है। जंजीरा के लोग जब हिंदू बस्तियों को उजाड़ते थे,तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन पर प्रहार कर बस्तियों को पुनः रोशन किया था। आज फिर वही समय लौट आया है–हमें आतंक की जड़ों तक जाना होगा।

विश्व में कोई भी आतंकवादी न स्वयं चैन से रहता है, न ही किसी और को जीने देता है। क्या हम बार-बार इसी तरह पीड़ित होते रहेंगे? सिर्फ आतंकियों को पकड़ लेने से क्या आतंकवाद समाप्त हो जाएगा? क्या सैलानी,पर्यटक भविष्य में निश्चिंत होकर कश्मीर या देश के किसी भी पर्यटन स्थल पर घूम सकेंगे?

हमें अब केवल टहनियाँ नहीं,जड़ें काटनी होंगी। चार-दस या सौ आतंकवादी केवल मोहरे हैं। मजहब, लालच और कट्टरता के नाम पर इन्हें उकसाया जाता है। अब वक्त है कि सीधे आतंक की जड़ पर प्रहार हो–विचारधारा की, प्रशिक्षण केंद्रों की, फंडिंग स्रोतों की और वैचारिक पोषण की।

इस दुःखद क्षण में एक संतोषजनक पहल यह रही कि घटना के तुरंत बाद देश के गृहमंत्री स्वयं घटनास्थल पर पहुँचे। यह पहली बार हुआ जब इतनी त्वरित प्रतिक्रिया केंद्र सरकार द्वारा देखने को मिली। यह दर्शाता है कि सरकार और एजेंसियाँ सजग हैं, लेकिन सवाल अब भी कायम है–क्या आगे निर्दोषों की जान बख्शी जाएगी?

हमने पूर्व में 26/11, संसद हमला, अमरनाथ यात्रा पर हमला और अनेक बार आतंक का घिनौना चेहरा देखा है। लेकिन अब वक्त है,जब भारत केवल रक्षात्मक नहीं,बल्कि प्रभावी प्रतिरोधात्मक रणनीति अपनाए।

क्या करना चाहिए?

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजहबी आतंकवाद के विरुद्ध भारत को नेतृत्वकारी भूमिका निभानी चाहिए।

घृणा और हिंसा फैलाने वाले ऑनलाइन नेटवर्क और फंडिंग चैनलों पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

आतंकवाद को वैचारिक समर्थन देने वाले नेताओं और संगठनों की शिनाख्त कर उन्हें निष्कासित करना चाहिए।

भारत की सुरक्षा नीति में 'रिएक्टिव' नहीं 'प्रो-एक्टिव' दृष्टिकोण अपनाना होगा।

भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है–

'शठं प्रति शाठ्यम्' – जो शठता से न माने, उसे उसकी ही भाषा में समझाना उचित है। अब भारत को भी यही करना होगा–जब तक आतंक की जड़ें जिंदा हैं, तब तक हर पेड़ हर शाखा हर पत्ता संदिग्ध है।

यह हमला केवल पहलगाम में नहीं हुआ है, यह हमला भारत की आत्मा पर हुआ है। और अब भारत को उत्तर देना होगा– शब्दों से नहीं, संकल्प से।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

लेखक व्यंग्यकार हैं।

समझदारी : एक अपडेट जो कभी डाउनलोड नहीं होती

कहते हैं उम्र के साथ समझदारी आती है। लेकिन हमारे यहाँ उम्र सिर्फ़ चश्मे का नंबर, बालों की सफेदी और घुटनों का दर्द लाती है। समझदारी? वो तो बचपन में ही किसी सरकारी योजना की तरह 'लॉन्च' होकर गायब हो जाती है। जिम्मेदारी और उम्र का रिश्ता भी अजीब है–कभी दोनों गलबहियाँ डालकर चलते हैं, कभी एक-दूसरे से आँखें चुराते हैं। और इस आँख-मिचौली में जिंदगी बस तमाशबीन बनी तालियाँ बजाती रहती है।

ज़रा गुड्डू को देखिए। चौदह साल की उम्र, लेकिन जिंदगी का टाइमटेबल किसी ग्लोबल कंपनी के सीईओ को भी मात दे। सुबह साइकिल पर अखबार बाँटता है, मानो हाई-स्पीड डिलीवरी ड्रोन पर सवार हो, दिन में स्कूल की बेंच घिसता है, जहाँ टीचर 'पढ़ाई करो, जिम्मेदार बनो' का प्रवचन देते हैं और रात को माँ का सिर दबाकर सुलाता है, जैसे 24×7 स्टार्टअप का वन-मैन-आर्मी हो, क्योंकि 'बाबूजी ने तो कब का फोन स्विच ऑफ कर लिया'। पूछो तो मासूमियत से कहेगा, 'जिम्मेदारी ने पकड़ लिया, भैया।' मानो जिम्मेदारी कोई पुलिसवाला हो, जो बिना वारंट धर दबोच ले। गुड्डू की उम्र में बच्चे जहाँ पबजी खेलते हैं, वहाँ ये जिंदगी का 'सर्वाइवल मोड' खेल रहा है।

अब दूसरी तरफ हैं हमारे प्रदीप चाचाजी। उम्र 60 पार, सरकारी नौकरी से रिटायर्ड, पेंशन की गंगा बह रही है। लेकिन जिम्मेदारी? वो तो उनके लिए 'अननोन कॉलर' है, जिसे वो बार-बार रिजेक्ट कर देते हैं। गैस सिलेंडर बुक करना हो तो बीवी को पुकारते हैं–'सुनो, वो मोबाइल में कुछ कर दो न!' यूपीआई, ओटीपी, ऑनलाइन बिल पेमेंट–ये सब उनके लिए एलियन टेक्नोलॉजी है। लेकिन फेसबुक? वहाँ सुबह 6:30 बजे 'गुड मॉर्निंग' के साथ गुलाब की फोटो और 'ज़िंदगी दो पल की, जी लो' वाला स्टेटस डालने में पीएचडी कर रखी है। व्हाट्सएप पर 'फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स' वाले मैसेज की स्पीड देखकर तो लगता है, चाचाजी 5जी नेटवर्क पर चल रहे हैं। जिम्मेदारी इनके दरवाजे तक दस्तक देती है, पर चाचाजी 'नॉट होम' का बोर्ड लगाकर अखबार फड़फड़ाते हुए चाय की चुस्कियाँ लेते रहते हैं।

यहाँ जिम्मेदारी भी तो ऑनलाइन शॉपिंग की तरह है। किसी को बिना ऑर्डर किए ही थमा दी जाती है, जैसे गुड्डू को। और किसी को बार-बार रिक्वेस्ट करने पर भी 'आउट ऑफ स्टॉक' का मैसेज मिलता है, जैसे चाचाजी को। छोटे बच्चों को देखकर जिम्मेदारी का दिल पसीज जाता है–'लो, तुम ही संभाल लो ये बोझ, तुम्हारे बाप-दादा तो रील्स बनाने में व्यस्त हैं।' और कुछ बुजुर्गों को देखकर वो शर्म से पानी-पानी हो जाती है–'इतने साल हो गए, अब भी नहीं संभाल सकते? ठीक है, बच्चों को ही दे देते हैं।' ये जिम्मेदारी भी न, व्यक्ति देखकर आती है। कुछ को गले का हार बनकर गले पड़ती है, और कुछ के लिए वो 'रिटर्न पॉलिसी' वाला पैकेज है, जिसे वो तुरंत डिलीवरी बॉय को लौटा देते हैं।

हमारे देश में दो ही चीज़ें टाइम से पहले आती हैं–बालों में सफेदी और जिम्मेदारी। बाकी सब तो सरकारी स्कीम की तरह–घोषणा जोर-शोर से, डिलीवरी अगले जन्म में। लोग जिम्मेदारी से ऐसे भागते हैं जैसे रिश्तेदार की शादी में 'नेग' देने से। 'अरे, अब इस उम्र में क्या!' मानो जिम्मेदारी कोई फिटनेस चैलेंज हो और उम्र उनका मेडिकल सर्टिफिकेट। कुछ लोग तो जिम्मेदारी को देखकर वैसे ही मुकर जाते हैं, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर का सामान देखकर–'ये तो माँगा ही नहीं था!'

जिम्मेदारी के भी अपने टाइप हैं। कुछ जिम्मेदारियाँ 'डिज़र्व' की जाती हैं, जैसे गुड्डू अपनी माँ की देखभाल करता है। कुछ को 'डेलिगेट' कर दिया जाता है, जैसे चाचाजी सारा काम बीवी पर डाल देते हैं। और कुछ तो जिम्मेदारी को कचरे की पेटी में डंप करने के चैंपियन हैं, जैसे वो पड़ोसी, जो मोहल्ले की मीटिंग में बड़े-बड़े वादे करते हैं, मगर सफाई अभियान का वक्त आए तो 'बुखार चढ़ गया' का बहाना मारकर गायब हो जाते हैं।

समाज में जिम्मेदारी का बोझ भी अजीब तरह से बँटता है। बच्चों को स्कूल बैग के साथ-साथ घर का बोझ भी ढोना पड़ता है। जवानों को नौकरी, शादी, बच्चों की परवरिश–सब एक साथ संभालना पड़ता है। और बुजुर्ग? वो तो 'हमने तो अपना समय देख लिया' कहकर पार्क में टहलने निकल लेते हैं। फिर भी दुनिया कहती है, 'उम्र के साथ समझदारी आती है।' अरे भाई, यहाँ उम्र के साथ सिर्फ़ हड्डियों का दर्द, आँखों का धुंधलापन और 'वो पुरानी बात याद नहीं आ रही' वाला बहाना आता है। जिम्मेदारी निभाने की नीयत? वो तो जन्मकुंडली में ही नहीं लिखी होती।

पहलगाम आतंकी हमला

बृजमोहन श्रीवास्तव

राष्ट्रीय महामंत्री-प्रभारी जम्मू-कश्मीर व प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता,नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी

कश्मीर में आतंक के विरुद्ध जन-आक्रोश की नई लहर

इसी दिन अनंतनाग में जयपुर के एक मुस्लिम जोड़े को भी गोली मार कर घायल किया था । इन दोनों घटनाओं के पीछे भारत सरकार के सुरक्षा प्रयासों के दावों को झुठलाने की कोशिश के साथ पर्यटकों को हतोत्साहित करने का उद्देश्य आतंकवादियों का था । पहलगाम में हुआ यह हमला बैसरन नामक घास के मैदान में हुआ,जहाँ केवल पैदल या टट्टू से ही पहुँचा जा सकता है, मंगलवार की सुबह पर्यटकों का एक समूह वहाँ घूमने गया था। इस हमले में निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या ने केवल मानवता को ही शर्मसार नहीं किया है बल्कि कश्मीर की शांति और विकास की राह में एक गंभीर चुनौती भी पेश करने की कोशिश की है जो उनकी हताशा को बयां करती है।

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में कम से कम 26 नागरिक मारे गए, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे । यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला है। इसके पहले 18 मई 2024 में भी दो आतंकवादी हमले हुये थे जिसमें शोपियां में बीजेपी के पूर्व सरपंच ऐजाज अहमद शेख की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, रात 10:30 बजे हिरपोरा में हुई इस घटना का उद्देश्य केंद्र सरकार के सुरक्षा प्रयासों से उपजी बौखलाहट थी । इसी दिन अनंतनाग में जयपुर के एक मुस्लिम जोड़े को भी गोली मार कर घायल किया था। इन दोनों घटनाओं के पीछे भारत सरकार के सुरक्षा प्रयासों के दावों को झुठलाने की कोशिश के साथ पर्यटकों को हतोत्साहित करने का उद्देश्य आतंकवादियो का था। पहलगाम में हुआ यह हमला बैसरन नामक घास के मैदान में हुआ,जहाँ केवल पैदल या टट्टू से ही पहुँचा जा सकता है, मंगलवार की सुबह पर्यटकों का एक समूह वहाँ घूमने गया था। इस हमले में निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या ने केवल मानवता को ही शर्मसार नहीं किया है बल्कि कश्मीर की शांति और विकास की राह में एक गंभीर चुनौती भी पेश करने की कोशिश की है जो उनकी हताशा को बयां करती है।

इस त्रासदी के बीच मगर एक सकारात्मक परिवर्तन भी देखने को मिला है। घटना के तुरंत बाद जिस प्रकार से कश्मीर के आम नागरिकों ने इस हमले की खुलकर निंदा की है और आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है जो इसके पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने रैलियाँ निकालकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, जो इस बात का संकेत है कि अब कश्मीर के लोग शांति और विकास के पक्षधर हैं और केन्द्र की नीतियों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में शांति और विकास का जो माहौल बना है, उसने स्थानीय लोगों को यह महसूस कराया है कि स्थिरता और समृद्धि ही उनके भविष्य की कुंजी है। पर्यटन, शिक्षा, और व्यापार के क्षेत्र में हुए सुधारों ने लोगों को यह समझाया है कि आतंकवाद से दूरी बनाकर ही वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।

कश्मीर के वातावरण में यह बदलाव अचानक नहीं आया है यह परिणाम केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी की नीतियों और प्रयासों से सम्भव हुआ है जो वह गत कई वर्षों से कर रहे है। उनके ईमानदार प्रयासों ने कश्मीर के लोगों में विश्वास और सुरक्षा की भावना को पुनर्जीवित किया है। पिछले समय से श्री शाह ने कश्मीर के बहुत से दौरे के दौरान स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित किया, कश्मीरियों के मन में यह भरोसा जगाया कि केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा व भलाई के लिए प्रतिबद्ध है।

पहलगाम की घटना पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी विदेश दौरे पर रहते हुए इस पर सतत निगरानी रखी । वहीं अपने विदेशी दौरे को बीच में छोड़कर कर यह स्पष्ट संदेश दिया कि कश्मीर की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार गंभीर है। घटना के तत्काल बाद श्री अमित शाह जी के पहुँचने से कश्मीर में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बना है लोगों को विश्वास हुआ है कि केंद्र के शांति के प्रयासों में कोई कमी नहीं आयेगी। उनके इस कदम से निश्चित ही आतंकियों के मनोबल पर असर पड़ेगा ।

बैसरन की घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या आतंकवाद फिर से पैर पसारने की कोशिश कर रहा है ? इसका जवाब निश्चित ही नहीं है क्योंकि अब कश्मीर के लोग जागरूक हो चुके हैं और उन्होंने तय कर लिया है कि वे आतंकवाद का समर्थन नहीं करेंगे। उनकी यह दृढ़ता ही आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि इस घटना के बाद कश्मीर में जो जन-आक्रोश देखने को मिला है, वह इस बात का प्रमाण है कि अब कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। यह बदलाव न केवल कश्मीर के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक आशा की किरण है।

यह अवसर है जब केंद्र सरकार इस जन-भावना को और मजबूत करे और कश्मीर के लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करे, ताकि वे आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और प्रभावी ढंग से लड़ सकें। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए।

अंततः, पहलगाम की घटना एक चेतावनी है, लेकिन कश्मीर के लोगों की प्रतिक्रिया एक आशा की किरण है जो केंद्र सरकार के प्रयासों पर सील लगाते हुये कह रही है कि अब समय आ गया है कि हम सभी मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों जिससे कश्मीर शांति, विकास, और समृद्धि की ओर अग्रसर हो जिससे आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके ।

रिश्ते और स्वाद

संजय तेलंग

(पत्रकार और स्तंभकार)

रसोई से गायब स्वाद और रिश्तों से मिठास

आज भोजन तैयार करने का काम आसान हो गया, लेकिन, रसोई घर में तैयार भोजन से मिलने वाला तृप्ति का रस गुम हो गया । इन नए उपकरणों ने रसोई घर से लकड़ी से जलने वाला चूल्हा, चूल्हे में आग भड़काने वाली फुंकनी, अनाज पीसने की घट्टी, सिलबट्टा, खल बत्ता जैसे पुराने देशी उपकरणों को रिप्लेस क्या किया रसोई से स्वाद ही रूठ गया ।

आधुनिक दौर में नित नए उपकरणों के आविष्कार और गैजेट्स ने लोगों का समय बचाकर उनका जीवन आसान बना दिया है। यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। रसोईघर मॉडर्न किचन बन गए, सोने का कमरा बेडरूम और बैठक हो गई है लिविंग रूम। लेकिन, सोचिये इस सबके बीच रसोई से स्वाद कहां चला गया और रिश्तों से मिठास कब गायब हो गई, यह तो पता ही नहीं चला। परिवार के बीच रहने वाले लोगों के पास अपनों के लिए ही समय नहीं है। उनके आपसी संबंध भी औपचारिक रह गए। क्या ऐसा नहीं लगता कि आधुनिक बनने या दिखने की होड़ में हमारा अपनापन न फिसल कर हमसे कहीं दूर चला गया है।

गैस का चूल्हा, चिमनी, मिक्सर-ग्राइंडर, माइक्रोवेव अवन, प्रेशर कुकर, एक्जास्ट फैन, वेजीटेबल चापर, फ्रिज जैसे उपकरणों से आज किचन में भोजन तैयार करने का काम आसान जरूर हो गया। लेकिन, रसोईघर में तैयार भोजन से मिलने वाला तृप्ति का रस न जाने कहां गुम हो गया। इन नए उपकरणों ने रसोई घर से लकड़ी से जलने वाला चूल्हा, चूल्हे में आग भड़काने वाली फुंकनी, अनाज पीसने की घट्टी, सिलबट्टा, खल बत्ता जैसे पुराने देशी उपकरणों को रिप्लेस क्या किया रसोई से स्वाद ही रूठ गया। अब वहां पेट भरने के लिए खाना बनाया जाता है, जिसमें नहीं होता है वह स्वाद जो मां-चाची के रसोई में बनाए भोजन में होता था।

रसोई घर में चूल्हे पर बनी रोटियों का स्वाद भला कोई कैसे भूल सकता है। इसी तरह सिलबट्टे पर पिसे खड़े मसाले और प्याज-लहसुन से बनी ग्रेवी का स्वाद तो वही बता सकता है, जिसने उससे तैयार सब्जी का लुत्फ उठाया हो। सिलबट्टे पर सिर्फ मसाले वाली सब्जी के लिए ग्रेवी का मसाला ही तैयार नहीं होता था, कैरी, पोदिना, खोपरा, हरी मिर्च, लहसुन की चटनी लजीज चटनी भी बनाई जाती थी। सिलबट्टे पर प्याज, खड़ा धनिया, खड़ी मिर्च सहित अन्य मसालों पीसने में काफी वक्त लगता था। सिल पर मसाले रख पूरी ताकत से बट्टे से उसे पीसा जाता था। पहले पूरा मसाला थोड़ा दरदरा करते, बाद में उसे महीन करते। इसमें काफी ताकत लगानी पड़ती थी, लेकिन

सब्जी खाने का लुत्फ भी तो हम ही उठाते थे। आज ग्राइंडर में झट से पिसे मसाले से तैयार सब्जी में वह स्वाद कहां !

पहले के रसोईघरों का जरूरी हिस्सा सिलबट्टा बार-बार मसाला पीसे जाने से चिकना हो जाता था। ऐसे में मसाला पीसने में दोहरी मेहनत लगती थी। लेकिन, इसका भी इलाज था। सिल टांकने वाले को बुलाकर कर सिल और बट्टे को टंकवाना। लोहे की छैनी और हथोड़ी से सैकड़ों प्रहारों के बाद सिलबट्टा नया हो जाता था। उस पर मसाला आसानी से पिसने लगता था। सिलबट्टे को टंकवाने की प्रक्रिया महीने-दो महीने की जरूरी एक्सरसाइज थी। इसके लिए मोहल्ले-बस्तियों में सिल टांकने वाले का इंतजार किया जाता था। क्योंकि, चिकने सिल पर मसाला पीसना टेढ़ी खीर से कम नहीं होता था।

दरअसल, हमारी मां-बहनें, चाची, भाभियां रसोई में जब भोजन तैयार करने का काम करती थीं, तो वहां से उठने वाली खुशबू ही आधा पेट भर देती थी। वे कुछ भी बनाती थी, उसमें स्वाद होता था। इस बारे में यह भी कहा जाता है कि किचन में पहले की महिलाओं की तरह अधिक समय बिताना आज की कामकाजी महिलाओं के लिए संभव भी नहीं है। उन्हें तो झटपट भोजन तैयार कर अपने काम पर भी जाना है। जबकि, स्वादिष्ट रसोई तैयार करने का पहला नियम ही है- मन से, आराम से और धीमी आंच पर भोजन तैयार किया जाए।

सिलबट्टे की चर्चा छेड़ने का लब्बोलुआब यह है, आज के साधन संपन्नता दौर में समय बचाने के लिए तो नए-नए प्रयोग हो रहे हैं, नए-नए उपकरण आ रहे हैं लेकिन रसोई में स्वाद और रिश्तों के बीच से गायब हुई मिठास को तलाशने के लिए कोई उपकरण नहीं बन रहा। वैसे, इस तरह के उपकरण बन भी नहीं सकते क्योंकि स्वाद का रिश्ता मन से है और रिश्ते इंसानों के बीच उपजते हैं मशीनों में भावनाएं नहीं हो सकती।

पहलगाम आतंकी हमला

हर्षवर्धन पाण्डे

लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं

धरती के स्वर्ग पर दहशत

द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के संगठन ने इस हमले जिम्मेदारी ली है जो लश्कर-ए-तैयबा की ही एक फ्रेंचाइजी है । आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा न केवल सुरक्षाबलों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि पर्यटकों और प्रवासी मजदूरों पर भी हमले कर रहे हैं । भारत के खिलाफ होने वाली हर साजिश को अंजाम देने में उसे पाक की सेना और कट्टरपंथी सगठनों का पूरा सहयोग मिल रहा है । यह तो बानगी भर है । जैश , हिज्बुल और लश्कर का पाक में अभी भी एक बड़ा नेटवर्क है । दुखद है जम्मू-कश्मीर में किसी भी बड़ी आतंकी घटना के तार सीधे इन्ही संगठनों से मिलते है और ये खुद ही आतंकी हमलों में अपनी संलिप्तता से पीछे नहीं हटते । पाक की महसूस कर रहा है अगर समय रहते उसने भारत के खिलाफ अपनी जंग शुरू नहीं की तो कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझ पाएगा । पाक के साथ भारत को अब किसी तरह की नरमी नहीं बरतनी चाहिए और आतंक के खिलाफ ठोस ऐक्शन लेने की जरूरत है ।

अपनी नैसर्गिक प्राकृतिक सुषमा और सुंदरता के लिए दुनिया भर में पहचाने जाने वाले जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि ने एक बार फिर हमारी सुरक्षा व्यवस्था, सामाजिक ताने-बाने और पर्यटन उद्योग पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस आतंकवादी घटना ने एक बार फिर से हमें झकझोर दिया है। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद कश्मीर में यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था जिसमें निशाने पर पर्यटक थे । इस आतंकी घटना ने 25 बरस पहले छत्तीसिंहपुरा नरसंहार की याद ताजा कर दी है। आतंकियों ने पहलगाम से करीब 6 किलोमीटर की दूरी के बैसरन के जिस इलाके को निशाना बनाया, यह इलाका घने देवदार के पहाड़ों से घिरा घास का बड़ा मैदान है। आतंकियों ने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि यहां अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं। खूबसूरत कश्मीर की फिज़ा को बिगाड़ने के लिए आतंकियों ने इस जगह को चुना। इन हमलों की प्रकृति में सुनियोजित रणनीति स्पष्ट दिखाई देती है।

द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के संगठन ने इस हमले जिम्मेदारी ली है जो लश्कर-ए-तैयबा की ही एक फ्रेंचाइजी है। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा न केवल सुरक्षाबलों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि पर्यटकों और प्रवासी मजदूरों पर भी हमले कर रहे हैं। भारत के खिलाफ होने वाली हर साजिश को अंजाम देने में उसे पाक की सेना और कट्टरपंथी सगठनों का पूरा सहयोग मिल रहा है । यह तो बानगी भर है। जैश, हिज्बुल और लश्कर का पाक में अभी भी एक बड़ा नेटवर्क है। दुखद है जम्मू-कश्मीर में किसी भी बड़ी आतंकी घटना के तार सीधे इन्ही संगठनों से मिलते है और ये खुद ही आतंकी हमलों में अपनी संलिप्तता से पीछे नहीं हटते। पाक की राजनीती का असल सच किसी से छुपा नहीं है। वहां पर सेना कट्टरपंथियों का हाथ की कठपुतली है। असल नियंत्रण सेना का हर जगह है। पाक यह महसूस कर रहा है अगर समय रहते उसने भारत के खिलाफ अपनी जंग शुरू नहीं की तो कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझ पाएगा। पाक के साथ भारत को अब किसी तरह की नरमी नहीं बरतनी चाहिए और आतंक के खिलाफ ठोस ऐक्शन लेने की जरूरत है।

2019 में धारा 370 के निरस्त होने के बाद भारत सरकार ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता स्थापित होगी लेकिन इस तरह की आतंकी घटनाएँ बताती हैं कि आतंकवादी गतिविधियाँ फिर से बढ़ रही हैं। सीमा पार से घुसपैठ और स्थानीय पर सहयोग इन हमलों का प्रमुख कारण हैं। आतंकी हमले हमारे सामाजिक सौहार्द को भी प्रभावित करते हैं। पर्यटकों को निशाना बनाए जाने से विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास और भय का माहौल बन सकता है।जम्मू और कश्मीर में देशी-विदेशी सैलानियों की तादाद पिछले वर्षों में लगातार बढ़ रही है। सड़क, रेल और हवाई यातायात के माध्यमों यह पूरे देश से जुड़ चुका है। बीते बरस 2.35 करोड़ से अधिक पर्यटक जम्मू-कश्मीर पहुंचे, जबकि अमरनाथ यात्रा में 5 लाख श्रद्धालु शामिल हुए। यही विकास आतंकियों को खटक रहा है। जिस कश्मीर को आर्टिकल 370 खत्म होने से पहले डर की भावना से देखा जाता था, वह अब पर्यटकों को लुभा रहा है। श्रीनगर का लाल चौक जहां कभी अलगाववादी देश विरोधी रैलियां निकालते थे, वहां अब सब खुली हवा में साँस ले सकते हैं। ऐसे में आतंकियों ने पर्यटकों पर निशाना बनाकर उनके मन में फिर से खौफ पैदा करने की कोशिश की है ।

आने वाले महीनों में पवित्र अमरनाथ यात्रा भी शुरू होनी है और उससे पहले माहौल बिगाड़ने से पूरी दुनिया का ध्यान कश्मीर पर एक बार फिर से केंद्र में आ सकता है। पहलगाम आतंकी हमले को सिर्फ एक घटना मानना भूल होगी, क्योंकि यह हमला पाकिस्तान की नई स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी हो सकता है। इस रणनीति का उद्देश्य है जम्मू क्षेत्र से होकर आतंकियों को भारत में प्रवेश कराना और धर्म के नाम पर नई दहशत फैलाना जिससे कश्मीर में आतंक की तसवीरें दिखाकर भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देना है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान की ओर से जम्मू सेक्टर के सामने 32 लॉन्च पैड्स में करीब 100 आतंकवादी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं, वहीं कश्मीर के सामने 10 लॉन्च पैड्स में सैकड़ों आतंकियों की मौजूदगी है। 2023 में 125 ड्रोन सीमा पार से भेजे गए, जबकि 2024 में यह संख्या 300 तक पहुंच चुकी है। इन ड्रोन्स के जरिए हथियार, विस्फोटक और संचार उपकरण पहुंचाए जा रहे हैं। 2022 में जहां 107 आतंकी घटनाएं हुई थीं, वहीं 2023 और 2024 में यह आंकड़ा घटकर क्रमशः 27 और 26 पर आ गया लेकिन पहलगाम से एक बार फिर जम्मू -कश्मीर में आतंक और हिंसा का नया तांडव शुरू हो सकता है।

पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर ने कश्मीर को लेकर अभी एक हफ्ते पहले ही अपना बयान दिया था। पहलगाम में पर्यटकों की इतनी बड़ी संख्या में निर्मम हत्या के पीछे सीधे-सीधे पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष असीम मुनीश की रणनीति भी हो सकती है। इस हमले से आतंकियों ने अमेरिका को भी संदेश देने की कोशिश की है कि कश्मीर अभी भी शांत नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या जटिल है। इसके समाधान के लिए खुफिया जानकारी के आधार पर त्वरित कार्रवाई, ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी, और स्थानीय पुलिस की क्षमता में वृद्धि आतंकी गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है। स्थानीय स्तर पर सहयोग मिले बिना आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकते यह हमें समझने की आज आवश्यकता है। स्थानीय लोग आतंकवादियों को गुप्त सूचनाएं प्रदान करते हैं और उन्हें छिपाने में मदद करते हैं। युवाओं को रोजगार और शिक्षा के नए अवसर प्रदान करके उन्हें आतंकी संगठनों की भर्ती से दूर रखा जा सकता है। स्थानीय समुदायों के साथ संवाद भी इस दिशा में महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करके सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित करने की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है।

जम्मू और कश्मीर में 2024 के आखिर में ही वर्षों के अंतराल के बाद एक लोकतांत्रिक सरकार बनी है। ऐसे समय में यह हमला और भी चिंताजनक है। आतंकवादी भारत में आतंकी हमलों के साथ धार्मिक अलगाव भी पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान की इस चाल को समझते हुए देश में अमन-चैन बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार और हमारी सेना आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेगी। हमारी सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मॉड पर हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पूरी स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं। इस संवेदनशील मौके पर सभी राजनीतिक दलों को एकजुटता दिखानी होगी। पाकिस्तान के मंसूबों को विफल करने और उसे कड़ा जवाब देने की रणनीति पर इस समय काम करना होगा। सरकार और नागरिकों को मिलकर इस खूबसूरत क्षेत्र को आतंकवाद के साये से मुक्त करना होगा, ताकि यहाँ शांति, समृद्धि और सामंजस्य का नया युग शुरू हो सके।

सी.एम.राइज विद्यालय बैतूल-बाजार में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न

बैतूल। सी.एम.राईज शा.कृषि उ.मा.वि.बैतूल-बाजार में बुधवार 23 अप्रैल को 2025 प्रवेश प्रक्रिया कक्षा पहली से पांचवी, छटवीं, नवमी, ग्यारहवीं संकायवार, माध्यमवार शासन के नियमानुसार संपन्न की गई। प्रवेश प्रक्रिया में मुख्य अतिथि विकासखंड शिक्षा अधिकारी आशीष

प्रहलादी, श्रीमती कुमुद थापलीयाल, सुरेंद्र राठौर सहित उपस्थित पालकों, विद्यार्थियों के समक्ष संपन्न की गई। प्रवेश प्रक्रिया में संस्था के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन उपस्थित अतिथि एवं प्राचार्य द्वारा किया गया। लॉटरी में चयनित विद्यार्थियों को तीन दिवस के भीतर संस्था में समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर प्रवेश लेना होगा, तीन दिवस के भीतर प्रवेश न लेने पर प्रतीक्षा सूची से विद्यार्थियों को अवसर दिया जाएगा। प्रवेश हेतु दिए गए समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति का मिलान मूल दस्तावेजों से किया जाएगा। दस्तावेजों में दी गई जानकारी में त्रुटि पाए जाने पर प्रवेश अमान्य होगा।

कलेक्टर ने जेईई में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का बढ़ाया उत्साह

बैतूल। जेईई की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी से भेंट की। इस अवसर पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने विद्यार्थियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें बधाई दी। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर व पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। कलेक्टर श्री

सूर्यवंशी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हमारे जिले के बच्चों को देखकर गर्व होता है। प्रशासन की यह कोशिश है कि हर बच्चा समान अवसर पाए और उसकी प्रतिभा को सही दिशा मिले। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आगामी जेईई एडवांस परीक्षा के लिए उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी अनिल कुशवाहा, सहायक संचालक सुबोध शर्मा और बच्चों को निशुल्क कोचिंग क्लासेस दे रहे विशेषज्ञ शिक्षक उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग द्वारा जिले में सतत निशुल्क जेईई कोचिंग क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ लेकर छात्र शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रथम चरण जनवरी एवं द्वितीय चरण अप्रैल में संपन्न परीक्षा के परिणाम को मिलाकर, अभी तक एकत्रित जानकारी अनुसार जिले से इन बच्चों में से 86 बच्चों को प्राप्त अंकों के आधार पर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलना संभावित है। यही नहीं इनमें से 28 बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने एडवांस परीक्षा के लिए क्वालीफाई किया है।जिले के ऐसे कई मेधावी छात्र, जो आर्थिक कारणों से बाहर जाकर महंगी कोचिंग नहीं ले सकते, उनके लिए सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्लेटफार्म तैयार किया गया है। इन निशुल्क कोचिंग क्लासेस के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वे अपने सपनों को साकार कर पा रहे हैं।

स्व. दुर्गाताई उमप का श्रद्धांजलि कार्यक्रम कल

बैतूल। शहर के सदर क्षेत्र में चंद्रशेखर वार्ड लिंक रोड बैतूल के निवासी उमप जनरल स्टोर्स के संचालकगण सुधीर एवं प्रवीण (पिंटू) उमप तथा जिला न्यायालय बालौद में कार्यरत सुनील उमप की

माताजी दुर्गाताई मधुकरराव उमप का गत 12 अप्रैल 2025 को 76 वर्ष की उम्र में दुखद निधन हो गया था। वे अपने पीछे तीन पुत्र, एक पुत्री-दामाद एवं नाती-पोते से भरापूरा परिवार छोड़ गई। जिनका चौदहवीं एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम शुक्रवार 25 अप्रैल 2025 को दोपहर 12 बजे से उनके निज निवास उमप जनरल स्टोर्स चंद्रशेखर वार्ड लिंक रोड सदर बैतूल में रखा गया है। श्रद्धांजलि एवं चौदहवीं कार्यक्रम के लिए शोकाकुल परिवार ने सभी से कार्यक्रम में शामिल होकर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करने का आग्रह किया है।

तुअर की खरीदी शुरू होने के 13 दिन बाद भी पोर्टल अपडेट नहीं

किसान मंडी में कम दाम पर बेच रहे तुअर

संजय द्विवेदी, बैतूल। जिले में पहली बार समर्थन मूल्य पर तुअर की खरीदी की जा रही है, लेकिन जिले में यह कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सका है। समर्थन मूल्य पर तुअर खरीदी की शुरुआत नहीं होने से जिले के किसानों को भटकना पड़ रहा है। किसान मंडी में जाकर कम दामों पर उपज बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हालांकि समर्थन मूल्य में तुअर बेचने के लिए करीब 80 किसानों ने पंजीयन करवाया है। किसान उपज बेचने के लिए लगातार संपर्क कर रहे है, किन्तु अभी तक पोर्टल पर इसकी जानकारी अपडेट नहीं हो सकी है। यहीं वजह है कि किसान कृषि मंडी में औने-पौने दाम पर अपनी तुअर की फसल बेचने को मजबूर हैं। बता दे कि समर्थन मूल्य पर तुअर बेचने के लिए 25 मार्च से किसानों के पंजीयन शुरू है, जो 20 अप्रैल तक हुए। सभी दसों ब्लॉकों में चार-चार सहकारी समितियों पर निःशुल्क पंजीयन किए गये। वहीं खरीदी के लिए जिले में एक खरीदी केंद्र तय किया है। यह बैतूल में इटारसी रोड आईटीआई के सामने वेयरहाउस के गोदाम में बना है। किसानों का कहना है कि इस वर्ष क्षेत्र में अधिकांश किसानों ने अन्य फसलों के साथ तुअर की फसल इस आशा के साथ लगाई थी कि तुअर के ठीक ढंग से भाव मिल जाएंगे। लेकिन अभी तक समर्थन मूल्य में खरीदी शुरू नहीं होने से किसानों को मंडी में तुअर की उपज बेचनी पड़ रही है। कृषि मंडी में 23 अप्रैल बुधवार को तुअर के न्यूनतम दाम 5000 से अधिकतम 6101 प्रति क्विंटल तक रहे, जबकि शासन ने तुअर का समर्थन मूल्य 7550 रुपये तय किया है। ऐसे में किसानों को सीधे-सीधे समर्थन मूल्य की अपेक्षा करीब एक हजार रुपये प्रति क्विंटल तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

5818 हेक्टेयर में तुअर की बोवनी- जिले में प्रशासन द्वारा तुअर की बोनी को लेकर गिरदावरी की गई है। इसमें जिले भर में 5818 हेक्टेयर में तुअर की बोवनी की गई है। 28 मार्च से 25 अप्रैल तक इसका सत्यापन होगा। आठनेर, भैंसदेही, प्रभातपट्टन, मुलताई, बैतूल सहित अन्य ब्लॉकों में तुअर की बोवनी किसानों ने की है। किसान रामप्रसाद ने बताया उन्होंने भी इस साल तुअर की बुआई की थी। अभी तक समर्थन मूल्य पर उपज

फाइल फोटो

बेचने के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन खरीदी शुरू नहीं हो सकी। अब मई माह के प्रथम सप्ताह में उनके घर शादी का कार्यक्रम है, ऐसे में उन्हें मंडी पर तुअर बेचनी पड़ रही है। किसान का कहना है कि मंडी में तुअर बेचने पर उन्हें प्रति क्विंटल एक हजार रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है।

कृषि मंडी में रोजाना हो रही तुअर की खरीदी - कृषि मंडी बडोरा में तुअर की आवक हो रही है। बुधवार को भी 17 क्विंटल आवक हुई। मंडी में किसानों को तुअर के न्यूनतम दाम 5000 से अधिकतम 6101 प्रति क्विंटल तक मिल रहे हैं, जबकि समर्थन मूल्य पर तुअर की खरीदी 7550 प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी, लेकिन कई किसानों को अभी तक इसकी जानकारी ही नहीं है। किसान कृषि मंडी में कम दाम पर तुअर बेचने को मजबूर है। ग्राम हिवरखेड़ी के किसान पवन राजपूत ने बताया 2 क्विंटल तुअर लेकर बेचने आए हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि समर्थन मूल्य पर तुअर की खरीदी होगी। इस वजह से मंडी में कम दाम में तुअर बेचना पड़ रहा है।

पोर्टल अपडेट नहीं होने से भी बढ़ी परेशानी- शासन ने 10 अप्रैल से तुअर खरीदी शुरू कर दी है, लेकिन जिले में अभी तक यह कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। इसके पीछे पोर्टल अपडेट नहीं होने को प्रमुख कारण माना जा रहा है। कृषि विभाग के एसडीओ रामवीर सिंह राजपूत ने बताया कि अभी 80 किसानों ने पंजीयन कराया है। श्री राजपूत ने बताया कि खरीदी पोर्टल पर कुछ एरर आ रहा था। अपडेट नहीं हो पा रहा है। इसलिए समिति प्रबंधक और ऑपरेटर की जानकारी फीड नहीं कर पाये। जैसे ही पोर्टल शुरू होगा, किसान स्लॉट बुक कर सकते है और उपज लाकर बेच सकते है। उम्मीद है कि एक-दो दिन में पोर्टल पर खरीदी शुरू हो जायेगी। वैसे खरीदी से संबंधित सभी चीजे आ चुकी है। केवल समिति प्रबंधक और ऑपरेटर की जानकारी फीड करना है।

कृषि उपज मंडी में 13527 बोरों की रही आवक- कृषि उपज मंडी बडोरा में बुधवार को कुल 13527 बोरों की आवक रही। जिसमें सोयाबीन 5397 बोरे, चना 275 बोरे, 4170 बोरे मक्का, 3606 बोरे गेहूं, 62 बोरे सरसो और तुअर की 17 बोरे आवक रही। कृषि उपज मंडी में रोजाना सोयाबीन, मक्का, चना, गेहूं, सरसो सहित तुअर की आवक हो रही है। बता दे कि इस साल शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर तुअर की खरीदी भी की जा रही है। किसानों ने इसके लिए पंजीयन कराया है, लेकिन पोर्टल अपडेट नहीं होने के कारण समर्थन मूल्य पर तुअर की खरीदी प्रारंभ नहीं हो पाई है। जिसके कारण किसान मंडी में तुअर उपज बेचने को मजबूर है।

इनका कहना है -

10 अप्रैल से तुअर खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन खरीदी को लेकर पोर्टल अपडेट नहीं हो सका है। उम्मीद है कि एक-दो दिन में पोर्टल अपडेट हो जायेगा, जिसके बाद किसान स्लॉट बुक कर उपज लाकर बेच सकते है। करीब तुअर बेचने के लिए 80 किसानों ने पंजीयन कराया है।

- रामवीर सिंह राजपूत,
सहायक संचालक, कृषि विभाग बैतूल

पंजीयन कम होने से गेहूं खरीदी का टारगेट 6 लाख क्विंटल घटाया

अब तक 1 लाख 97 हजार 800 क्विंटल ही हुई गेहूं की खरीदी, 3570 किसानों ने करवाई स्लॉट बुक

बैतूल। समर्थन मूल्य पर की जा रही गेहूं खरीदी में पंजीयन कम होने और स्लॉट बुकिंग करने वाले किसानों की संख्या के कारण टारगेट कम कर दिया है। जिले में पहले 9 लाख क्विंटल गेहूं खरीदने का टारगेट रखा था, जिसे घटाकर तीन लाख क्विंटल किया जा रहा है। यानि 6 लाख क्विंटल गेहूं खरीदने का टारगेट कम कर दिया है। जिले में इस बार 12 हजार 194 किसानों के पंजीयन हुए हैं। इनमें से अब तक तीन हजार किसानों से ही खरीदी हुई है। इस बार सरकारी खरीदी में 72 घंटे में भुगतान की प्रक्रिया लागू करने के

बाद भी अब तक तीन हजार किसानों से 1 लाख 97 हजार 780 क्विंटल गेहूं की खरीदी हुई है। गेहूं खरीदी की रफ्तार देखकर टारगेट को कम करने की प्रक्रिया शुरु हो गई है। जिले में गेहूं खरीदी का टारगेट 9 लाख क्विंटल रखा था, लेकिन स्लॉट बुक करवाने वालों की संख्या देखकर इसे घटाकर तीन लाख क्विंटल किया जा रहा है। नागरिक आपूर्ति निगम के जीएल लुधियानी ने बताया अब तक 3 हजार किसानों ही खरीदी हुई है। जबकि आने वाले दिनों के लिए 3577 किसानों ने ही स्लॉट बुक करवाए हैं। जितने किसानों ने स्लॉट बुक करवाए हैं, उसके अनुसार जिले में तीन लाख क्विंटल ही गेहूं खरीदा जा सकता है। इसके लिए खरीदी का टारगेट कम किया जा रहा है।

14 केंद्रों पर नहीं आया गेहूं- जिले में गेहूं खरीदी के लिए 64 केंद्र बनाए थे। इन केंद्रों में 50 पर ही अब तक खरीदी हुई है। जबकि 14 केंद्रों पर एक भी किसान नहीं पहुंचा। यह केंद्र आमला और मुलताई ब्लॉक के हैं। यहां के किसानों ने खरीदी होने के पहले ही व्यापारियों को गेहूं बेच दिया। इसके चलते यहां पर पंजीयन करवाने वाले किसान भी गेहूं नहीं बेच रहे।

34 करोड़ का हुआ भुगतान- इस बार किसानों को भुगतान भी 72 घंटे में किए जाने के निर्देश हैं। इसके चलते किसानों को भुगतान भी जल्द किया जा रहा है। अभी तक गेहूं बेचने वाले किसानों को कुल भुगतान 51 करोड़ 42 लाख होता है। इसमें से अब तक 34 करोड़ का भुगतान किसानों को हो चुका है। वहीं 43 करोड़ के ईपीओ भी जारी हो गया है। किसानों को भुगतान व्यवस्था भी बेहतर होने के बाद भी किसान मंडी या व्यापारियों को सीधे गेहूं बेच रहे हैं। इसके कारण जिले का टारगेट भी कम किया जा रहा है।

पृथ्वी मां के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने संगोष्ठी में जुटे समाजसेवी

जिला पंचायत सभागार में हुआ संगोष्ठी का आयोजन, पर्यावरण की रक्षा का लिया संकल्प

बैतूल। अंतर्राष्ट्रीय मातृ भूमि दिवस के अवसर पर 22 अप्रैल को मध्यप्रदेश राज्य आनंद संस्थान, आनंद विभाग द्वारा हमारी शक्ति, हमारा ग्रह थीम पर जिला पंचायत सभागृह में एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अक्षत जैन के मार्गदर्शन में आयोजित इस संगोष्ठी का विषय था हम सब अपनी पृथ्वी मां को कृतज्ञता प्रकट करने हेतु क्या दे सकते हैं। संगोष्ठी में 50 से अधिक बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और शासकीय-अशासकीय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद बैतूल की अध्यक्ष पार्वतीबाई बारस्कर रहीं, जबकि अध्यक्षता आनंद विभाग बैतूल के नोडल अधिकारी सतीष पंवार ने की। संगोष्ठी की शुरुआत मास्टर ट्रेनर दिलीप गीद द्वारा आनंद विभाग की गतिविधियों की जानकारी से हुई। उन्होंने नेकी की दीवार और प्रत्याशा आनंद क्लब की पहल का उल्लेख किया। क्लब की संचालिका तुलिका पचौरी ने क्लब की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। मुख्य अतिथि पार्वतीबाई बारस्कर ने कहा कि पृथ्वी मां के प्रति सच्ची कृतज्ञता यही होगी कि हम अपने नगर को स्वच्छ और हरा-भरा बनाए। उन्होंने सभी नागरिकों से स्वेच्छा से छोटे-बड़े कार्यों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की। ग्राम शिक्षक व समाजसेवी शैलेंद्र बिहारिया ने पर्यावरण के प्रति हमारे नकारात्मक प्रभाव को कम करने पर बल देते हुए कहा कि जल-संरक्षण, कचरा प्रबंधन, वृक्षारोपण और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग हमें अपनाना चाहिए। प्रदीपन संस्था की प्रमुख रेखा गुजरे ने पृथ्वी को अद्भुत ग्रह बताते हुए कहा कि यह हमें जीवन के लिए जरूरी हवा, पानी और भोजन देती है।

युवक को बेरहमी से पीटा, खून जमने से कई जगह से शरीर पड़ा काला

पीड़ित युवक जिला चिकित्सालय में भर्ती, पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ

बैतूल/आमला। जिले के आमला क्षेत्र में अवैध गतिविधियां एवं नशे के कारोबार के बढ़ने से युवा पीढ़ी इसकी गिरफ्त में फंसकर दलदल में जा रही है। ताजा मामले में सोमवार की शाम वार्ड क्रमांक पांच निवासी एक युवक मोहम्मद आसिफ वार्ड क्रमांक तीन स्थित ईदगाह दरगाह पर इबादत करने गया था, तभी वहां पहले से बैठे गांजा पी रहे तीन युवकों ने मोहम्मद आसिफ को बुरी तरह पीटा, जैसा कि पीड़ित के परिजनों और पुलिस ने हमारे संवाददाता को बताया है कि पहले तो आरोपी युवकों ने पीड़ित को जबरदस्ती गांजा पिलाने का प्रयास किया, फिर बेल्ट से उसको लगातार पीटते रहे तथा पास के ही एक नल के प्रेशर पाइप से उस पर पानी की बौछार भी की गई। जिसके चलते पीड़ित को कई गंभीर चोटें आई है। घटना रात लगभग 10 बजे की बताई जा रही है। वहीं जैसा कि बताया गया है कि पीड़ित युवक को गंभीर अवस्था में रात लगभग ढाई बजे घटनास्थल से उठाकर उसके परिजन आमला चिकित्सालय ले गए, जहां पर

मेडीकल होने के बाद पीड़ित की हालत गंभीर होने से उसे जिला चिकित्सालय बैतूल रेफर कर दिया गया है। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने उसकी जेब से 2 हजार रुपए और मोबाइल भी छीन लिया। इस घटना से नाराज मुस्लिम संगठनों ने स्थानीय पुलिस व्यवस्था पर काफी रोष जताते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कार्यवाही की मांग की है, हालांकि आमला पुलिस ने पीड़ित और उसके परिजनों की शिकायत के बाद हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा बताया गया है कि घटना के सभी तीन आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है।

इनका कहना है...

मामला संज्ञान में आते ही तत्परता से कार्यवाही करते हुए आरोपियों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की जा रही है, आरोपियों की संख्या तीन है जिनमें दीपक भोजेकर की पहचान भी की जा चुकी है, आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है।

- सत्यप्रकाश सक्सेना, थाना प्रभारी आमला*

जिले के आमला में युवक के साथ हुई गंभीर मारपीट के प्रकरण में पार्थी के आवेदन पर एफआईआर दर्ज करके तीन को हिरासत में ले लिया है जिनमें एक बालिग और दो नाबालिग शामिल हैं। उन्हें हिरासत में लेकर पलिस घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। पुलिस की जांच में इस प्रकरण में अभी तक किसी भी प्रकार की धर्म संबंधी बातों का होना नहीं पाया गया, बल्कि कुछ अन्य ही तथ्य सामने आ रहें हैं। हमारे द्वारा उन तथ्यों पर विस्तृत जांच की जा रही है।

- निश्चल एन झारिया,
एसपी बैतूल

अनिश्चितकालीन हड़ताल के दूसरे दिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को भेजे पोस्टकार्ड

पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में दिवंगत भारतीयों को दी श्रद्धांजलि

बैतूल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 22 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दूसरे दिन बुधवार को वादा निभाओ सरकार के तहत हजारों कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम पोस्टकार्ड भेजे, जिनमें संविदा नीति 2023 के तहत लाभ दिए जाने की मांग की गई। इस दौरान कर्मचारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महापंचायत का वीडियो पोस्टर लगाकर प्रोजेक्टर के माध्यम से देखा, जिसमें उन्होंने पूर्व में संविदा कर्मचारियों से किए गए वादों की चर्चा की थी। इसके अलावा भारतीय मजदूर संघ प्रांत समिति के सदस्य राजेश मंसूरिया एवं विद्युत कर्मचारी महासंघ के सचिव चंद्रभान पंडाग्रे ने अपने उद्बोधन से आंदोलन का मार्गदर्शन किया। बुधवार को आंदोलन का संचालन बीपीएम एकनाथ ठाकुर ने किया। साथ ही अनेक कर्मचारी संगठनों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन किया। हड़ताल के दौरान संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में दिवंगत भारतीयों को श्रद्धांजलि दी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. गोविंद साहू ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के द्वारा संविदा नीति 2023 का पूर्ण रूप से लाभ न प्रदान करते हुए कर्मचारियों की सुविधा में कटौती कर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश की आदेश की अव्हेलना कर कर्मचारियों के साथ बादा खिलाफी की गई है, जिसके विरोध में प्रदेश के समस्त 32 हजार एनएचएम कर्मचारी चरणबद्ध आदोलन के तहत 22 अप्रैल से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले गए है।

दो साल से बंद पड़ी नल-जल योजना, फिल्टर प्लांट भी बंद

योजना के लिए स्वीकृत हुए थे कुल 154.87 लाख रुपए

बैतूल/भौंरा। जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायत भौंरा में करीब डेढ़ करोड़ की लागत से बनाई गई नल-जल योजना दो साल से अधूरी और बंद पड़ी है। योजना के अंतर्गत बिछाई गई 9980 मीटर पाइपलाइन और फिल्टर प्लांट जैसे तमाम निर्माण कार्य होने के बावजूद गांव के एक भी घर तक शुद्ध पानी नहीं पहुंच पाया है। जिसको लेकर पत्रकार कल्याण परिषद जिला बैतूल अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार कैलाश प्रसाद अग्निहोत्री द्वारा सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के जरिए उच्च अधिकारियों को मुद्दे से अवगत कराया गया जिसके बाद ग्राम पंचायत भौंरा ने भी इस गंभीर लापरवाही को लेकर बैतूल कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। साथ ही ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और पेनाल्टी लगाने की मांग की गई है। वरिष्ठ पत्रकार श्री अग्निहोत्री द्वारा शासन को की गई शिकायत में बताया है कि किस प्रकार करोड़ों के कार्यों को पतीला लगाया गया एवं ग्रामीण आज दिनांक तक भी शुद्ध पेयजल से वंचित हैं। साथ ही पंचायत द्वारा दिए गए आवेदन में भी उल्लेख किया गया है कि पीएचई विभाग द्वारा ठेकेदार के माध्यम से बोर खनन, पाइपलाइन बिछाने और फिल्टर प्लांट निर्माण जैसे कार्य पूरे कर लिए गए, लेकिन योजना को चालू नहीं किया गया और न ही इसे पंचायत को हैंडओवर किया गया। फिल्टर प्लांट निर्माण के बाद से ही बंद पड़ा है,

जिससे गांव में शुद्ध जल आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी।

न घरों में नल, न पोल, सडक़ किनारे बिखरे हैं नीले पाइप- योजना की स्थिति देखकर साफ है कि यह सिर्फ कागजों पर पूरी हुई है। गांव के एक भी घर में नल के पोल या स्टैंड नहीं लगाए गए हैं। जिन स्थानों पर नल लगाए जाने थे, वहां नीली पाइपें खुली पड़ी हैं। कई जगहों पर पाइपलाइन अधूरी है और खुले में नजर आती है। इससे योजना की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस योजना पर कुल 154.87 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। इसके अंतर्गत बोर खनन, पंप हाउस, फिल्टर प्लांट, पाइपलाइन, स्टोरेज और घर-घर कनेक्शन जैसी व्यवस्थाएं की जानी थीं। लेकिन आज भी गांववाले गर्मी में पीने के पानी के लिए हैंडपंप और कुओं पर निर्भर हैं।

सिर्फ कागजों पर पूरी हुई योजना- ग्राम पंचायत भौंरा की सरपंच मीरा धुर्वे ने कहा फिल्टर प्लांट, पाइपलाइन और बोर की व्यवस्था होने के बाद भी दो साल से पीने के लिए एक बूंद पानी गांव नहीं पहुंचा है। पंचायत ने पीएचई से कई बार पत्राचार किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कलेक्टर से सीधी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय ग्रामीण रामलाल यादव ने बताया हमारे गांव में फिल्टर प्लांट के साथ ही पाइप तो बिछा दिए हैं, लेकिन पीने के लिए पानी कभी नहीं आया। नल नहीं लगे, पाइप खुले में पड़े हैं। गर्मी में हैंडपंप भी जवाब देने लगे हैं। ठेकेदार ने सिर्फ पैसा लिया, गांव को कुछ नहीं दिया।

हमने ठेकेदार को नोटिस भेजा था, जिस पर सोमवार को उनके प्रतिनिधियों ने फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया है। विभाग योजना को जल्द चालू कराने की प्रक्रिया में है।

- योगेश धुर्वे, एसडीओ, पीएचई विभाग शाहपुर

प्रसिद्ध दुनावा राम मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण, मंदिर में हुई भगवान राम प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा

बैतूल/मुलताई। क्षेत्र के ग्राम दुनावा में स्थित प्रसिद्ध राम मंदिर जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण हो गया है। मंदिर के पूर्ण होने पर बुधवार को रामकथा के साथ भव्य नवनिर्मित राम मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण एवं सीता की प्रतिमा का पूरी धार्मिक रीति रिवाज के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर का कार्य पूर्ण होने के बाद राम मंदिर परिसर में सात दिवसीय संगीतमय राम कथा सत्संग का आयोजन किया गया था। राम कथा का प्रारंभ कलश यात्रा से हुआ था, जिसका समापन पंडित रामकिशोर शास्त्री द्वारा किया गया किया गया। इस भव्य आयोजन में दुनावा सहित दर्जनों ग्राम के ग्रामीणों ने भाग लिया शोभायात्रा और भंडारा प्रसादी ग्रहण कर इस पवित्र दिन के साक्षी बने। इस अवसर पर श्री रामजी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान राम की शोभायात्रा दुनावा ग्राम के विभिन्न गलियों, मोहल्लों और ग्राम के सभी मंदिरों से होते हुए राम मंदिर पहुंची, जहां पं श्री राम किशोर शास्त्री द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। श्रद्धालु डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों पर नृत्य करते हुए जय घोष कर रहे। कार्यक्रम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें

आसपास के दर्जनों गांव से सैकड़ों महिलाओं पुरुषों और बच्चों ने प्रसाद ग्रहण किया।

200 वर्ष में दो बार हुआ मंदिर का जीर्णोद्धार- दुनावा में स्थित प्रसिद्ध राम मंदिर अत्यंत प्राचीन मंदिर माना जाता है। प्राचीन मंदिर की स्थिति बिगड़ने के चलते इसके जीर्णोद्धार के लिए मंदिर से जुड़े श्रद्धालु आगे आए और जन सहयोग से श्री राम सेवा धर्मार्थ लोक न्यास ट्रस्ट के माध्यम से श्री राम मंदिर का दूसरी बार जीर्णोद्धार हुआ है। ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने बताया कि इसके पहले 40 वर्ष पूर्व जीणोद्धार हुआ था। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 70 लाख की लागत लग चुकी है और लगभग 10 लाख रुपए का कार्य और होना बाकी है।

राम नाम जपने से होता है सभी कष्टों का निवारण- कथा वाचक महंत सीताराम दास ने कहा कि प्रभु श्री राम की लीलाओं से प्रेरणा लेकर समाज की बुराइयों को दूर करना चाहिए, उन्होंने बताया कि राम नाम के जप से सभी कष्टों का निवारण होता है राम कथा श्रवण से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। महंत जी ने कहा कि प्रभु राम ने हर लीला में धर्म की मर्यादा का पालन किया, उन्होंने जीवन में संयम और सदाचार का महत्व समझाया शास्त्रों के अनुसार मर्यादा का पालन करने वाले को परमात्मा की प्राप्ति होती है। कथा के सातवें दिन कथा के अलावा हवन पूजन धार्मिक कार्यक्रम चलते रहे। जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु महिला और पुरुष शामिल रहे। राम कथा के अंतिम दिन श्री राम प्राण प्रतिष्ठा और हवन पूजन, कन्या भोज, विशाल भंडारा एवं प्रसाद वितरण हुआ इसमें आजू-बाजू के गांव से सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए।

एमईआईएल को मिली परमाणु विद्युत परियोजना

भोपाल। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हैदराबाद स्थित कंपनी को भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड से कर्नाटक में दो 700 मेगावाट के परमाणु रिएक्टर - कैगा यूनिट 5 और 6 के निर्माण के लिए 12,800 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। यह परियोजना न केवल एमईआईएल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्ध्ढ्ढरुका लक्ष्य इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करना और भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में योगदान देना है।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने ई-एचआरएमएस मॉड्यूल की समीक्षा की

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय भोपाल में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल (ई-एचआरएमएस) की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मॉड्यूल मध्यप्रदेश सरकार की स्थानांतरण नीति के सिद्धांतों एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि स्थानांतरण नीति का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करते हुए प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मॉड्यूल में सभी आवश्यक मापदंडों का समावेश इस तरह से किया जाए कि किसी भी कर्मचारी को अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश में कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लागू प्रतिबंध अगले कुछ दिनों में हटाया जाने वाला है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसी समयावधि को ध्यान में रखते हुए ई-एचआरएमएस मॉड्यूल की अंतिम टेस्टिंग पूर्ण कर ली जाए, ताकि प्रतिबंध हटते ही स्थानांतरण प्रक्रिया बिना किसी बाधा, सुगमता और पारदर्शिता के साथ संचालित की जा सके।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि यह मॉड्यूल प्रदेश में मानव संसाधन प्रबंधन को तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि कर्मचारियों के बीच विश्वास भी सुदृढ़ होगा। आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री तरुण राठी, विभागीय अधिकारी, एमपीएसईडीसी के तकनीकी टीम के सदस्य उपस्थित थे।

नर्स लीड क्लिनिक पहल के लिए एम्स भोपाल में डब्ल्यूएचओ प्रतिनिधि का दौरा

भोपाल। 22 अप्रैल 2025 को एम्स भोपाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन,कंट्री ऑफिस, नई दिल्ली की नेशनल प्रोफेशनल ऑफिसर, डॉ. रक्षिता खानिजौ द्वारा नर्सिंग कॉलेज, एम्स भोपाल की नर्स लीड क्लिनिक पहल का दौरा किया गया। यह पहल भारत में नर्सिंग स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक

महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस अवसर पर डॉ. रक्षिता खनिजो ने मरीजों, छात्रों और संकाय सदस्यों से संवाद किया तथा एम्स भोपाल के नर्सिंग कॉलेज द्वारा की जा रही सराहनीय पहल की प्रशंसा की। उन्होंने नर्स लीड क्लिनिक के माध्यम से प्रदान की जा रही सहृदय संवाद और साक्ष्य-आधारित नर्सिंग देखभाल की सराहना की, जो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में प्रभावी, रोगी केंद्रित देखभाल के एक आदर्श मॉडल के रूप में उभर रही है।

इस अवसर पर प्रो. (डॉ.) अजय सिंह, कार्यपालक निदेशक एवं सीईओ, एम्स भोपाल ने भारत में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में नर्सिंग पेशे और गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा नर्स लीड क्लिनिक पहल, प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य सेवा में नर्सों की विकसित होती भूमिका का प्रमाण है। इस तरह के नवोन्मेषी मॉडल हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करते हैं एवं सुलभ और न्यायसंगत रोगी देखभाल के लिए एक आधार के रूप में काम करते हैं। कार्यक्रम में प्रो. अमित अग्रवाल, डीन (नर्सिंग एंड पेरमेडीक्स) और डॉ. सैकत दास, एसोसिएट डीन (नर्सिंग एंड पेरमेडीक्स) ने भी भाग लिया। उन्होंने बीते तीन वर्षों में नर्सिंग कॉलेज की अकादमिक और अनुसंधान उपलब्धियों को रेखांकित किया, जो नर्सिंग शिक्षा और अंतर्विषयक अनुसंधान में संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह दौरा नर्स लेड क्लिनिक से संबंधित संकाय, नोडल अधिकारी और समग्र संकाय समन्वयक डॉ. लिली पोद्दार (एसोसिएट प्रोफेसर) द्वारा समन्वित किया गया। यह दौरा नर्सिंग शिक्षा और समग्र रोगी देखभाल में उत्कृष्टता की दिशा में संस्थान की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है।

इवनिंग वॉक पर निकले बुजुर्ग के हाथ से मोबाइल छीना

पुलिस ने दो दिन बाद दर्ज की एफआईआर, आरोपी फरार

भोपाल (नप्र)। भोपाल में इवनिंग वॉक पर निकले बुजुर्ग के हाथ से मोबाइल झपटने का मामला सामने आया है। घटना 20 अप्रैल की शाम की है। पुलिस ने फरियादी से आवेदन लेकर जांच की, जिसके बाद मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात एफआईआर दर्ज की गई है।फिलहाल आरोपियों का सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। घटना स्थल के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पिपलानी थाना पुलिस ने बताया कि 71 साल के सुदर्शन शर्मा भवानी धाम कॉलोनी में रहते हैं। रोजाना की तरह घटना के दिन भी शाम करीब साढ़े छह बजे वह पैदल टहलते हुए छत्रसाल नगर से गुजर रहे थे। इसी बीच बाइक सवार तीन बदमाश उनके नजदीक पहुंचे और हाथ में लिया मोबाइल फोन छीनकर भाग निकले।

आतंकवादी हमले के विरोध में पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला जलाकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

कायरतापूर्ण हमले को भारत का मुस्लिम समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा: सनवर पटेल

भोपाल । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री सनवर पटेल के नेतृत्व में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में बुधवार को भोपाल स्थित मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड परिसर में पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। श्री सनवर पटेल के नेतृत्व में मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आतंकवाद के खात्मे के लिए देश की राष्ट्रपति के नाम भोपाल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष एम एजाज खान, मोर्चे के जिला अध्यक्ष श्री शहरयार अहमद, जिला वक्फ कमेटी अध्यक्ष श्री इरशाद अंसारी, श्री असलम इलयास, श्री रमीज कुरैशी सहित समाज के लोग उपस्थित रहे।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री सनवर पटेल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में हिंदू भाइयों के आस्था के केंद्र धार्मिक स्थल हैं। कश्मीर का मुसलमान भी इन हिंदू धार्मिक स्थलों की यात्रा में सदैव हिंदू भाइयों का सहयोगी रहा है। मंगलवार को कश्मीर के पहलगाम से कुछ दूरी पर स्थित बैसरन घाटी में हिंदुओं पर किए गए कायराना आतंकवादी हमले की मध्यप्रदेश का मुस्लिम समाज सहित मैं भर्त्सना करता हूं।

इस्लाम निर्दोषों की हत्या की शिक्षा नहीं देता- भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री सनवर पटेल ने कहा कि पहलगाम के पास जिस तरीके से आतंकवादियों ने निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम किया है, उससे संपूर्ण भारत का मुस्लिम समुदाय बहुत आहत है, क्योंकि इस्लाम कभी भी निर्दोषों की हत्या की शिक्षा नहीं देता। आज भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों में मुस्लिम समाज आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान का पुतला जलाया है और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए हमले से सारा देश दहल गया है। हर भारतीय को गहरा दुख और पीड़ा पहुंची है। इस तरह के घिनौने कृत्य की हम सभी कड़ी निंदा करते हैं।

हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा- भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री सनवर पटेल ने कहा कि कश्मीर में कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले को मध्यप्रदेश का मुस्लिम समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे हिंदू भाई-बहनों के लिए अमरनाथ यात्रा का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों पर हमला अमानवीय और घिनौना कृत्य के साथ मानवता के खिलाफ है। हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उसका समर्थन करने वाले पाकिस्तान की हम घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद शांति, सद्भावना और विकास का दुश्मन है। हम दोषियों पर शीघ्र सख्त सजा की मांग और इन आतंकवादियों के पनाहगार पाकिस्तान पर भी कड़ी कार्यवाही की मांग करते हैं। इस दुख की घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और आतंकवाद के खिलाफ एक जुट होकर लड़ने का संकल्प लेते हैं।

माखनलाल पत्रकारिता विवि में होगी फिल्मों की प्रदर्शनी

अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने किया पोस्टर का विमोचन

भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के सिनेमा एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा 24 और 25 अप्रैल 2025 को 'सिनेब्रेशन2.0' का आयोजन किया जा रहा है। यह दो दिवसीय आयोजन विश्वविद्यालय के गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार में होगा, जिसमें फिल्म प्रदर्शनियों के साथ-साथ फिल्मों पर आधारित सांस्कृतिक

कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। 2024 में शुरू हुए इस आयोजन का यह दूसरा वर्ष है, जो छात्रों की रचनात्मकता और तकनीकी कौशल को प्रदर्शित करने का एक अनूठा मंच प्रदान करता है।

'सिनेब्रेशन 2.0' के पोस्टर का विमोचन प्रख्यात बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने किया था। उन्होंने इस अवसर पर छात्रों को सामाजिक और समकालीन विषयों पर फिल्म निर्माण के लिए प्रेरित किया और उनकी रचनात्मकता की सराहना की। इस आयोजन के माध्यम से सिनेमा विभाग के छात्रों द्वारा निर्मित उत्कृष्ट लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और समकालीन मुद्दों पर आधारित हैं। ये फिल्में दर्शकों को विचारोत्तेजक अनुभव प्रदान करेंगी और समाज के विभिन्न पहलुओं पर नई दृष्टि डालेंगी। इस वर्ष आयोजन की थीम 'रेट्रो' रखी गई है, जो 1990 के दशक की सिनेमाई शैली को आधुनिक प्रारूप में रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करेगी। इस थीम के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नृत्य, संगीत और नाटक शामिल होंगे। ये कार्यक्रम दर्शकों को उस दौर की सिनेमाई संस्कृति का आनंद लेने का अवसर प्रदान करेंगे। सिनेमा एवं जनसंपर्क विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवित्र श्रीवास्तव ने कहा, नेब्रेशन2.0 का उद्देश्य छात्रों की रचनात्मकता, तकनीकी कौशल और कहानी कहने की कला को प्रोत्साहित करना है।

सिनेमा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गजेन्द्र अवास्या ने बताया कि प्रदर्शित होने वाली फिल्में सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों से गहराई से जुड़ी हैं। ये फिल्में आधुनिक दृष्टिकोण के साथ दर्शकों को समाज के बदलते परिदृश्य से रूबरू कराएंगी।

मिशन परिवार विकास पखवाड़े में लक्ष्य दंपत्तियों तक पहुंच रहे स्वास्थ्य कार्यकर्ता

भोपाल। परिवार कल्याण सेवाओं के लिए जागरूकता एवं स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए संचालित मिशन परिवार विकास पखवाड़े में परिवार नियोजन के स्थाई एवं अस्थाई साधनों की सेवाएं लक्ष्य दंपत्तियों तक पहुंचाई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले द्वारा नसबंदी, आईयूसीडी, अंतरा इंजेक्शन, ओरल पिल्स , छाया गोली, निरोध के उपयोग के लिए हितग्राहियों को जानकारी देकर प्रेरित किया जा रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत पिछले साल 12088 नसबंदी ऑपरेशन किए गए थे, जबकि 4855 आईयूसीडी एवं पीपीआईयूसीडी, 766 अंतरा साधन लगाए गए थे।

पखवाड़े में नव विवाहित दंपत्तियों को विवाह का पंजीयन करवाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही नवदंपत्तियों को नई पहल किट प्रदान की जा रही है। इस किट में महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधन, परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी एवं कंडोम व गर्भनिरोधक गोलियां दी जाती हैं। साथ ही प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी प्रदान की जाती है।

जागरूकता रैलियों के माध्यम से परिवार कल्याण साधनों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही विवाह के दो साल बाद पहला बच्चा, पहले बच्चे के जन्म के 3 साल बाद दूसरा बच्चा एवं दो बच्चों के बाद नसबंदी करवाने संबंधी जानकारी भी दी जा रही है। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा नसबंदी करवाने के इच्छुक दंपतियों की सूची तैयार कर नजदीकी स्वास्थ्य संस्था में आयोजित नसबंदी शिविरों में नसबंदी करवाई जा रही है। परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत जिला चिकित्सालय में महिला एवं पुरुष नसबंदी प्रतिदिन की जा रही है। साथ ही अंतरा इंजेक्शन भी प्रतिदिन लगाए जा रहे हैं। सिविल अस्पताल डॉ कैलाशनाथ काटजू में एलटीटी, सीटीटी, एलएससीएसटीटी सहित परिवार नियोजन के सभी अस्थाई साधनों की सेवा प्रतिदिन दी जा रही है। सिविल अस्पताल बैरागढ़ में परिवार नियोजन के सभी स्थाई एवं अस्थाई साधन सेवाएं प्रतिदिन उपलब्ध है । नसबंदी एवं अस्थाई साधनों की सुविधा एम्स चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, गैस राहत चिकित्सालय, खुशीलाल आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कस्तूरबा चिकित्सालय एवं चिन्हित निजी चिकित्सा संस्थाओं में भी दी जा रही है ।

सुल्तानिया जनाना चिकित्सालय एवं इंदिरा गांधी गैस राहत चिकित्सालय में प्रतिदिन महिला नसबंदी हो रही हैं। इसके अतिरिक्त फिक्स्ड डे सर्विसेज के तहत सिविल अस्पताल बैरसिया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांधीनगर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलार ,जवाहरलाल नेहरू गैस राहत चिकित्सालय, कस्तूरबा चिकित्सालय में निर्धारित दिवसों में नसबंदी ऑपरेशन किए जा रहे हैं। साथ ही विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सा संस्थाओं में भी नसबंदी की सुविधा निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि मिशन परिवार विकास पखवाड़े में नवविवाहित दंपतियों एवं दो बच्चे वाले दंपतियों को परिवार कल्याण कार्यक्रम की जानकारी देने के प्रयास विशेष रूप से किए जा रहे हैं। जिससे कि वे परिवार कल्याण कार्यक्रम में सही समय पर सक्रिय भूमिका निभा सकें । शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में पुरुष नसबंदी करवाने पर 3 हजार, प्रसव पश्चात महिला नसबंदी पर 3 हजार, अंतराल नसबंदी करवाने पर 2 हजार, पीपीआईयूसीडी लगवाने पर 300 एवं अंतरा इंजेक्शन लगवाने पर 100 रुपए हितग्राही को दिए जाते हैं। मिशन परिवार विकास पखवाड़े में लक्ष्य दंपत्तियों तक पहुंच रहे स्वास्थ्य कार्यकर्ता।

नवदंपत्तियों को दी नई पहल किट - परिवार कल्याण सेवाओं के लिए जागरूकता एवं स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए संचालित मिशन परिवार विकास पखवाड़े में परिवार नियोजन के स्थाई एवं अस्थाई साधनों की सेवाएं लक्ष्य दंपत्तियों तक पहुंचाई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले द्वारा नसबंदी, आईयूसीडी, अंतरा इंजेक्शन, ओरल पिल्स , छाया गोली, निरोध के उपयोग के लिए हितग्राहियों को जानकारी देकर प्रेरित किया जा रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत पिछले साल 12088 नसबंदी ऑपरेशन किए गए थे, जबकि 4855 आईयूसीडी एवं पीपीआईयूसीडी, 766 अंतरा साधन लगाए गए थे।

पखवाड़े में नव विवाहित दंपत्तियों को विवाह का पंजीयन करवाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही नवदंपत्तियों को नई पहल किट प्रदान की जा रही है। इस किट में महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधन, परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी एवं कंडोम व गर्भनिरोधक गोलियां दी जाती हैं। साथ ही प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी प्रदान की जाती है।

जागरूकता रैलियों के माध्यम से परिवार कल्याण साधनों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही विवाह के दो साल बाद पहला बच्चा, पहले बच्चे के जन्म के 3 साल बाद दूसरा बच्चा एवं दो बच्चों के बाद नसबंदी करवाने संबंधी जानकारी भी दी जा रही है। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा नसबंदी करवाने के इच्छुक दंपतियों की सूची तैयार कर नजदीकी स्वास्थ्य संस्था में आयोजित नसबंदी शिविरों में नसबंदी करवाई जा रही है।

आबकारी अधिनियम की धारा 47 असंवैधानिक घोषित

हाईकोर्ट की फुल बेंच ने कहा-कलेक्टर को नहीं वाहन राजसात करने के अधिकार, यह ट्रायल कोर्ट का काम

जबलपुर (नप्र)। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की फुल बेंच ने कलेक्टर के उस आदेश को विलोपित करते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जिसमें अभी तक अपराध में शामिल वाहन को राजसात करने का अधिकार कलेक्टर के पास हुआ करता था। मंगलवार को मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत, जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस विवेक जैन ने आबकारी अधिनियम की धारा को असंवैधानिक करार दिया है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वाहन को राजसात करने का अधिकार अब जिले के कलेक्टर को नहीं बल्कि संबंधित ट्रायल कोर्ट को होगा। सागर निवासी राजेश विश्वकर्मा और तेंदूखेड़ा निवासी रामलाल झारिया की ओर से यह याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट विवेक रंजन पांडे, जयंत नीखरा, संजीव नीखरा ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा।

सुनवाई में अधिवक्ता विवेक रंजन पांडे ने कोर्ट को बताया कि आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47 के तहत वाहन को राजसात करने का अधिकार कलेक्टर को है। इसी तरह गोवंश अधिनियम 2004 में दिए उस प्रावधान को भी चुनौती दी गई थी, जिसमें अपराध में शामिल वाहन को राजसात करने का अधिकार कलेक्टर को था। अलग-अलग बेंच में लगे इन मामलों को कई बार उठाया गया, जिसके चलते वैधानिक प्रश्न के निराकरण के लिए फुल बेंच को यह केस रेफर किया गया।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता विवेक रंजन ने दलील दी कि-कई बार मालिक की मर्जी बिना भी वाहन का उपयोग होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि चोरी के वाहन से शराब सप्लाई की जाती है, जिसे कि आबकारी विभाग या फिर पुलिस कई बार पकड़ भी लेती है। लंबी ट्रायल के चलते राजसात वाहन कंडम हो जाते हैं और उनकी नीलामी हो जाती है। कई लोग

तीन जजों की विशेष पीठ ने यह निर्णय दिया है कि कलेक्टर को आपराधिक प्रकरण में सजा दिए जाने से पहले, जब्त हुए वाहन को राजसात करने का अधिकार नहीं है। धारा 47 में दिया गया अधिकार असंवैधानिक है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सजा दिए जाने के बाद ही वाहन को राजसात किया जा सकता है, इससे पहले की गई कार्रवाई असंवैधानिक होगी।

ऋण लेकर वाहन खरीदते हैं। वाहन जब्त होने से मालिक को अपूर्णीय क्षति होती है।

अधिवक्ता विवेक रंजन पांडे ने बताया कि सागर के याचिकाकर्ताओं ने एक्साइज एक्ट की धारा 47 की संवैधानिकता को उच्च न्यायालय में चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस सहित दो अन्य जस्टिस की विशेष पीठ ने मामले की सुनवाई की। फुल बेंच ने एक्साइज एक्ट की धारा 47 को असंवैधानिक घोषित किया है। कलेक्टर क्रिमिनल ट्रायल होने के पहले ही उन वाहनों को राजसात कर लेते थे, जो एक्साइज एक्ट के तहत अवैध शराब ले जाते समय जब्त होते थे।

अधिवक्ता विवेक रंजन पांडे ने बताया कि हाईकोर्ट की फुल बेंच के इस ऐतिहासिक फैसले से, उन लोगों को लाभ पहुंचेगा, जिनके वाहन बिना वजह ही राजसात हो जाते थे। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश का असर खनिज, वन, कस्टम सहित उन विभागों पर भी पड़ेगा, जहां पर कि वाहनों के राजसात की कार्रवाई की जाती है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसे मामलों में वाहन राजसात करने के अधिकार अब सिर्फ न्यायिक मजिस्ट्रेट को होंगे। हाईकोर्ट का यह आदेश उन सभी लंबित मामलों पर प्रभावी होगा जिसमें आज तक जिला दंडाधिकारी ने राजसात या जब्ती का आदेश नहीं दिया है।

नयी पीढ़ी पढ़ रही है इसलिए उम्मीद भी है

भोपाल। विश्व पुस्तक दिवस के उपलक्ष्य में समता ट्रस्ट ने जहांगीराबाद स्थित लोहिया सदन लाइब्रेरी में पुस्तक व पत्र-पत्रिकाओं की प्रदर्शनी व चर्चा का आयोजन किया ।

लोहिया सदन लाइब्रेरी की निदेशक डॉ शिवा श्रीवास्तव के संयोजन में हुए इस आयोजन में माधवराव सप्रे समाचारपत्र संग्रहालय के संस्थापक विजयदत्त श्रीधर , साहित्यकार मुकेश वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर विशेष रूप से उपस्थित थे। पुस्तक - प्रदर्शनी का विमोचन पूर्व - पार्षद श्रीमती बिलकिस जहां व भोपाल की गणमान्य महिलाओं ने किया। अध्यक्षता लोहिया सदन के संस्थापक समाजवादी चिंतक व राजनेता रघु ठाकुर ने की। विजयदत्त श्रीधर व मुकेश वर्मा का सम्मान समता ट्रस्ट की ओर से मदन जैन व डॉ शिवा श्रीवास्तव ने किया।

लोहिया सदन पुस्तकालय के विषय में बताते हुए रघु ठाकुर ने कहा कि सन् 1985 में समाजवादी राजनेता मधु लिमए के हाथों शुरू हुए इस पुस्तकालय के लिए ललितपुर के डॉ शादीलाल दुबे का विशेष सहयोग रहा। उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पच्चीस हजार रुपए की एफडी कराई थी।? वे जब नहीं रहीं तो यह धनराशि लोहिया सदन को सौंप दी। आज लोहिया सदन में डा. शादीलाल दुबे के नाम से एक कक्ष है व एक डॉ विजय देव नारायण साही के नाम से। रघु ठाकुर ने कहा कि बड़े राजनीतिक दलों के भवन जिन ट्रस्टों से संचालित हैं उनपर नाममात्र का सम्पत्ति कर लगता है जबकि लोहिया सदन पर उससे कई गुना ज्यादा लगता है। व्यवस्था इस तरह का भेदभाव करती है।

रघु ठाकुर ने कहा कि पहले यहां पुस्तकें गोदाम की तरह अटी पड़ी थीं, पुस्तकालय की शक्ल बहुत मेहनत से डॉ शिवा श्रीवास्तव ने दी। निराशा के दौर में डा. लोहिया की किताब निराशा के कर्तव्य पढ़ने की जरूरत उन्होंने बताई।

माधवराव सप्रे समाचारपत्र संग्रहालय के संस्थापक विजयदत्त श्रीधर ने कहा कि पहले राजनेता पुस्तकालयों में बैठते थे तो सदन में अच्छी और तार्किक बहसें होती थीं। आजादी की लड़ाई के समय पुस्तकालय ही विचार विमर्श के केन्द्र होते थे। पुस्तकें अब भी पढ़ी जा रही हैं जिससे उम्मीद जगती है।

साहित्यकार श्री मुकेश वर्मा ने कहा कि कौन सी किताब प्राथमिकता से पढ़ी जाये यह समझ विकसित होना जरूरी है।

राजनीतिक विश्लेषक व पत्रकार गिरिजा शंकर ने कहा कि देश में नौजवान खूब पढ़ रहे हैं और कैरियर की चिंता किए बिना खूब रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े भी हैं। इसे देखकर लगता है कि मुल्क पटरी पर आ जाएगा।

आयोजन में सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पंचायती राज के विशेषज्ञ श्याम बोहरे ने कहा कि केरल जैसे राज्य में शिक्षा का स्तर इसलिए भी ऊंचा है कि वहां गांव गांव में पुस्तकालय हैं।

लोहिया सदन के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए समता ट्रस्ट के अध्यक्ष मदन जैन ने बताया कि लोहिया सदन अनेक शुभचिंतकों की मदद से बना है और नियमित रूप से विमर्श व समाज हित के कार्यक्रम आयोजित करता है।कार्य क्रम से मुख्य रूप से मकसूद भाई, पंकज पाठक, इरशाद खान, साजिद हाशमी, जयंत तोमर, अनिल गिदवानी, ,वसीम उपस्थित रहे।

॥ मंदिरम् ॥

91

भोगनंदीश्वर और अरुणाचलेश्वर मंदिर, कर्नाटक

भोगनंदीश्वर मंदिर और अरुणाचलेश्वर मंदिर कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले के नंदी गांव में स्थित एक जुड़वां हिंदू मंदिर परिसर हैं। अलंकृत, खूबसूरती से नक्काशीदार और शिव को समर्पित, इनका समय विभिन्न प्रकार से 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच का बताया गया है। मंदिर परिसर में दो बड़े मंदिर हैंः भोगनंदीश्वर और अरुणाचलेश्वर मंदिर। उनकी वास्तुकला बहुत समान है, लेकिन बिल्कुल एक जैसी नहीं है। दोनों के दक्षिण में स्थित 'अरुणाचलेश्वर' मंदिर नया है और इसमें थोड़ी अधिक जटिल कलाकृति है। दोनों एक बड़े प्रांगण और खुले सभा-मंडप को साझा करते हैं। प्रत्येक के पास एक नवरंगा, एक अंतराल, एक सुकनासी, एक गर्भगृह और एक द्रविड़शैली का विमान है। बरोठा और हॉल जाली नामक छिद्रित पत्थर की स्क्रीन से सुसज्जित हैं। प्रत्येक मंदिर के सामने एक नंदी मंडप है (नंदी बैल की मूर्तिकला छविवाला हॉल) जो गर्भगृह के सामने है।

पहलगाम हमले के खिलाफ एमपी में सड़कों पर उतरे लोग

आतंकवाद और पाकिस्तान के पुतले जलाए

भोपाल (नप्र)। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकी हमले में 27 पर्यटकों की मौत के बाद देशभर में गुस्सा है। लोग सड़कों पर उतरकर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश में भी लोगों ने आतंकवादियों की इस कायराना हरकत की निंदा की है। भोपाल में जय हिंद सेना ने भारत माता चौराहे पर प्रदर्शन किया, तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला जलाया।

भोपाल के चार बत्ती चौराहे पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान 'आतंकवाद मुर्दाबाद' और 'मोदी जी 56 इंच का सीना दिखाना होगा' जैसे नारे लगाए गए। इंदौर में धर्म रक्षा समिति ने आतंकवाद के खात्मे का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर आतंकवादियों को फांसी देने की मांग की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। इस कुकृत्य का मुंहतोड़ जवाब आतंकियों को जरूर मिलेगा। पूर्व सीएम कमलनाथ और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी इस हमले की निंदा की है।

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बोले- इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता

मप्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने कहा- इससे शर्मनाक इंसानियत के विरुद्ध कोई काम हो नहीं सकता। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जो इस षड्यंत्र के पीछे हैं वो अपने कुप्रयास में कभी कामयाब नहीं होंगे। देश की जनता इस बात को कभी स्वीकार नहीं करती। इसी का परिणाम है कि देश भर में आज मुसलमान भाई बाहर निकले हैं। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं।

पाकिस्तान और दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत एकजुट : सीएम यादव

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में इंदौर निवासी श्री सुशील नथानियल की असामयिक मृत्यु पर गहन शोक व्यक्त किया। उन्होंने बाबा महाकाल से दिवंगत पुण्यात्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को मीडिया को जारी संदेश में कहा कि श्री सुशील नथानियल अलीराजपुर में एलआईसी कार्यालय में पदस्थ थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि वे स्वयं इंदौर में श्री नथानियल की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रदेश सरकार हमले में घायल श्री नथानियल की बेटी आकांक्षा की मदद के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है। दुख की इस घड़ी में सरकार मृतक के परिवार के साथ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह सहित पूरा केंद्रीय नेतृत्व इस मामले पर पल-पल नजर रखे हुए हैं। कश्मीर में पर्यटकों पर हमला पाकिस्तान की कायराना हरकत है। यह घटनाक्रम पूरे देश पर वज्रपात के समान है। पाकिस्तान और उसके हिमायती दहशतगर्दों को इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरा देश एकजुट है।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने केन्द्रीय कानून एवं न्याय, (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत किया।

भाजपा सांसद सुमेर सिंह का मीडिया हैंडलर लापता

कसरावद पुल पर मिली बाइक-चप्पल, शादी से 7 दिन पहले नर्मदा में कूदने की आशंका

बड़वानी (नप्र)। राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी के मीडिया हैंडलर महेंद्र भाटी के लापता होने का मामला सामने आया है। महेंद्र ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी और फिर गायब हो गए। फिलहाल, कोतवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम नर्मदा नदी में तलाश अभियान चला रही है। कसरावद स्थित नर्मदा नदी के बड़े पुल पर उनकी मोटरसाइकिल और चप्पल बरामद हुई है। पुलिस को आशंका है कि उन्होंने नर्मदा नदी में छलांग लगा दी है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग और शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। महेंद्र भाटी के पिता गोपाल भाटी ने बताया कि उसकी शादी 1 मई को होने वाली थी। विवाह पत्रिका भी बंट चुकी थी। शादी महेंद्र की पसंद से तय की गई थी और तैयारियां चल रही थीं। महेंद्र ने अपनी आखिरी फेसबुक पोस्ट में लिखा, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं स्वयं हूं, इसलिए मेरे नहीं रहने के बाद किसी को भी परेशान नहीं किया जाए। नर्मदे हर...।

सुबह निकले थे घर से- महेंद भाटी सुबह अपने घर ग्राम कल्याणपुरा से करीब 8.30 बजे निकले थे। 10 बजे उन्होंने फेस बुक पर पोस्ट की। जैसे ही दोस्तों और रिश्तेदारों ने पोस्ट देखी वे नर्मदा नदी के कसरावद पुल पर पहुंच गए। यहां उन्हें महेंद्र की बाइक खड़ी मिली।

मंडीदीप में गेल प्लांट से गैस लीक

10 घंटे की मशक्कत के बाद रोका जा सका रिसाव, जयपुर से सेफ्टी टीम जांच करने पहुंची

मंडीदीप (नप्र)। भोपाल के नजदीकी मंडीदीप में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे गेल प्लांट में गैस लीक हो गई। गैस लीक की सूचना मिलते ही फायर सेफ्टी टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद बुधवार सुबह करीब 10 बजे रिसाव को रोका जा सका। इस दौरान प्लांट के अंदर अफरा-तफरी मची रही।

एहतियातन एनडीआरएफ और एसडीईआर की टीमें भी मौके पर पहुंची। प्लांट के एक किलोमीटर के दायरे में बैरिकेड्स लगाकर आवाजाही पर रोक लगा दी गई। नगर पालिका मंडीदीप के फायर फाइटर्स को बुला लिया गया। इलाके को खाली करा लिया गया। सतलापुर और मंडीदीप पुलिस, होमगार्ड की टीम भी तैनात रही।

प्रोजेक्ट मैनेजर बोले- स्थिति नियंत्रण में- गेल के प्रोजेक्ट मैनेजर डी डोंगरे ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है। उन्होंने कहा- रिसाव को नियंत्रित कर लिया गया है। किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं है। स्कूलों की छुट्टी या आसपास के क्षेत्र को खाली कराने जैसी कोई आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा, एसडीएम चंद्रशेखर श्रीवास्तव, एसडीपीओ शीला सुरणा और नायब तहसीलदार नीलेश सरवटे ने प्लांट का जायजा लिया है।

कलेक्टर बोले- सेफ्टी ऑडिट करा रहे- कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने कहा- प्लांट में मिड नाइट से गैस रिसाव हो रहा था। हमें इसकी जानकारी सुबह करीब पांच बजे मिली। अब रिसाव रोक दिया गया है। पूरे एरिया को सैनिटाइज कराया गया है। हालत गंभीर नहीं हैं। हम प्लांट का सेफ्टी ऑडिट करा रहे हैं। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए सेफ्टी एसओपी तैयार करेंगे। एसपी पंकज पांडे ने कहा- प्लांट की सेफ्टी जांच की जा रही है। इसके बाद गैस लीक के कारणों का पता लगाया जाएगा।

घरों और उद्योगों का पीएनजी सप्लाई होती है

मंडीदीप में गेल का प्लांट शासकीय सिविल अस्पताल के पास है। यहां एलएनजी को पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) में कन्वर्ट करके पाइपलाइन से घरों और इंडस्ट्रीज में सप्लाई किया जाता है। यहां से कंपनी डोमेस्टिक, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल गैस की सप्लाई करती है। प्लांट में घरेलू गैस 750 एससीएम, कॉमर्शियल 1600 एससीएम और इंडस्ट्रियल 7500 एससीएम की स्टोर कैपेसिटी है।

दो साल पहले भी लीक हुई थी गैस

करीब दो साल पहले भी गेल प्लांट से गैस का रिसाव हुआ था। प्लांट में सीएनजी गैस में मरकैप्टन लिक्विड मिलाया जा रहा था। इसी दौरान 6 इंच पाइप में बचे हुए लिक्विड की 10 से 12 बूंदें नीचे गिर गईं। इस केमिकल की गंध इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में करीब आधा किलोमीटर दूर सतलापुर में पहुंच गई थी। लोगों को आंखों में जलन, जी मचलाना, उल्टी और चक्कर की समस्या हुई थी।

आदमपुर में कई घंटे से सुलग रही आग

भोपाल की सबसे बड़ी कचरा खंती, 10 किमी दूर से दिख रहा धुआं

भोपाल (नप्र)। भोपाल की सबसे बड़ी आदमपुर कचरा खंती में पिछले 24 घंटे से आग सुलग रही है। इससे आसपास के गांवों में धुआं ही धुआं है। यह 10 किलोमीटर दूर भोपाल से भी दिखाई दे रहा है। धुएं की वजह से ग्रामीणों की आंखों में जलन भी हो रही है।

अब तक करीब तीन लाख टन कचरे में आग लग चुकी है। कचरे का धुआं पड़रिया, बिलखिरिया, शांति नगर, समरधा, अर्जुन नगर, हरिपुरा व छावनी के लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है, क्योंकि कई लोगों को आंखों में जलन हो रही है। जनपद सदस्य संतोष प्रजापति ने बताया कि धुएं की वजह से रातभर सो नहीं सके। सुबह भी धुआं निकल रहा है। खंती के आसपास करीब 12 हजार आबादी रहती है।

एक दिन पहले लगी थी भीषण आग

बता दें कि आदमपुर कचरा खंती में एक दिन पहले मंगलवार दोपहर 1 बजे भीषण आग लग गई थी। आग बेकाबू हो गई थी। हालांकि, रात तक यह काबू में आई, लेकिन कचरा अधिक होने से यह फिर से सुलग गई। बुधवार दोपहर में भी धुआं निकल रहा है।

भोपाल से हर रोज निकल रहा 800 टन कचरा

जानकारी के अनुसार, भोपाल में हर दिन 800 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। एक्सपर्ट के मुताबिक, कचरे की पूरी प्रोसेसिंग नहीं होती। सूखा कचरा सीमेंट प्लांट को नहीं भेजा जा रहा। इससे खंती में कचरा इकट्ठा होता रहा और तापमान बढ़ने से मीथेन गैस बनी। इससे आग भड़की, जो अब तक पूरी तरह से नहीं बुझ सकी है।

118 किमी की पंचक्रोशी यात्रा में नई तकनीक का इस्तेमाल

पहली बार लगे कैमरे, भीड़ को संभालने के लिए मैसेजिंग सिस्टम

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन में वैशाख मास की दशमी से अमावस्या तक चलने वाली पंचक्रोशी यात्रा आज से शुरू हो गई है। यह यात्रा 27 अप्रैल तक चलेगी। इस बार की पंचक्रोशी यात्रा के लिए जिला प्रशासन ने सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए पहली बार यात्रा रूट पर पांच जगह हेड काउंटिंग कैमरे लगाए गए हैं।

पहली बार यात्रा में ऑटोमैटिक मैसेजिंग सिस्टम लगाया गया है। इसके जरिए एक ही जगह से सभी पड़ावों पर एक साथ मैसेज भेजे जा सकेंगे। कंट्रोल रूम से भी मैसेज का आदान-प्रदान किया जा सकेगा।

एक दिन पहले शुरू की 118 किमी की यात्रा- उज्जैन में श्रद्धालुओं ने परंपरागत रूप से एक दिन पहले 22 अप्रैल से ही यात्रा शुरू कर दी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद यात्रा के पहले पड़ाव पिंगलेश्वर महादेव के लिए निकल पड़े। पांच दिन तक चलने वाली यात्रा की शुरुआत 23 अप्रैल से होनी थी लेकिन एक दिन पहले 22 अप्रैल को ही पटनी बाजार स्थित श्री नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर पर भारी भीड़ पहुंच गई।

नागचंद्रेश्वर से शुरू, शिप्रा स्नान के साथ समापन- पांच दिवसीय यह यात्रा उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर से शुरू होकर पिंगलेश्वर, करोहन, अंबोदिया, जैथल और उंडासा से होते हुए लौटेगी। यात्री इस दौरान शहर के चारों कोनों में बने मंदिर पिंगलेश्वर, कायावर्णेश्वर, विल्वेश्वर, दुर्दरेश्वर, नीलकंठेश्वर का पूजन-अर्चन करेंगे।

शनि मंदिर त्रिवेणी, राघौपिपल्या, नलवा, सोडंग और केडी पैलेस जैसे उपपड़ाव भी इसमें शामिल रहेंगे। समापन नागचंद्रेश्वर मंदिर लौटने के बाद शिप्रा नदी में स्नान के साथ होगा।

पहली बार 6 स्थानों पर करेंगे हेड काउंटिंग- क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए इस बार पड़ाव स्थलों सहित यात्रा रूट पर 6 जगह हेड काउंटिंग मशीनें लगाई गई हैं। इन मशीनों के जरिए यह पता लगाया जा सकेगा कि प्रत्येक पड़ाव पर कितने श्रद्धालु पहुंचे? कहां सबसे अधिक भीड़ है और किस स्थान पर भीड़ को डायवर्ट करने की जरूरत है।

सीसीटीवी कैमरों के साथ ऑटोमैटिक मैसेजिंग सिस्टम भी- जिला पंचायत सीईओ जयति सिंह ने बताया- हेड काउंटिंग मशीन उन पड़ावों पर लगाई गई हैं, जहां लोग एक लाइन में निकल रहे हैं। ऐसी 6 जगह चिह्नित कर कैमरे लगाए हैं।

माह के आखिरी में भीषण गर्मी का अलर्ट

पैर न जले इसलिए महाकाल मंदिर में बिछाई मेटिंग, इंदौर में चौराहों पर टेंट लगे

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में अप्रैल के आखिरी दिनों में भीषण गर्मी का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत कई शहरों में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच सकता है, जबकि खजुराहो, नौगांव, पन्ना, सीधी में तापमान 45 डिग्री या इससे अधिक रह सकता है। वहीं, लू भी चलेगी।

तेज गर्मी की वजह से इंदौर के कई चौराहों पर टेंट लगा दिए गए हैं। ताकि, राहगीरों को राहत मिल सके। वहीं, उज्जैन स्थित श्री महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं के पैरों को जलने से बचाने के लिए मेटिंग बिछाई गई है। इधर, बुधवार को प्रदेश के 6 जिलों में लू का अलर्ट है। इनमें निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, सीधी और सिंगरौली जिले शामिल हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत अन्य शहरों में भी तेज गर्मी रहेगी।

खजुराहो में पारा 44.4 डिग्री पहुंचा, रतलाम भी गर्म रहा- प्रदेश में मंगलवार को तेज गर्मी का असर देखा गया। छतरपुर के खजुराहो में पारा 44.4 डिग्री रहा, जबकि रतलाम में 44 डिग्री दर्ज किया गया। सीधी में 43.4 डिग्री, मंडला में 43 डिग्री और नौगांव में 43 डिग्री रहा। प्रदेश के 5 बड़े शहरों में भी पारा 2 डिग्री तक बढ़ गया। जबलपुर सबसे गर्म रहा। यहां तापमान 42 डिग्री रहा। भोपाल में 41.2 डिग्री, इंदौरमें 40.9 डिग्री, ग्वालियर में 41.5 डिग्री और उज्जैन में 41.5 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा 40 डिग्री के नीचे रहा। बाकी जिलों में इससे अधिक ही दर्ज किया गया। इनमें नर्मदापुरम, दमोह-मलाजखंड में 42.6 डिग्री, टीकमगढ़ में 42.4 डिग्री, खरगोन, सागर-नरसिंहपुर में 42.2 डिग्री, उमरिया-धार में 42.1 डिग्री, सिवनी, गुना-शिवपुरी में 42 डिग्री, सतना में 41.8 डिग्री, शाजापुर में 41.7 डिग्री, रीवा में 41.6 डिग्री, छिंदवाड़ा में 41.4 डिग्री, रायसेन-बैतूल में 41.2 डिग्री और खंडवा में 40.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

पारे में बढ़ोतरी का दौर रहेगा- सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया, प्रदेश में अभी मौसम साफ है। इस वजह से गर्मी का असर बढ़ा है। अगले 5 से 6 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा।

ऐसा रहेगा अप्रैल का आखिरी सप्ताह - चौथा सप्ताहः उत्तर-पश्चिमी हवाओं के लगातार जोर पकड़ने के साथ न्यूनतम तापमान पूरे प्रदेश में सामान्य से 3-4 डिग्री अधिक यानि 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। दिन के साथ रातें भी गर्म हो जाएंगी। ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग में पारा 43-45 डिग्री जबकि इंदौर, उज्जैन-भोपाल सहित बाकी प्रदेश में 41 से 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रह सकता है। बंगाल क्षेत्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से अप्रैल के आखिरी में 3 से 4 दिन तक लू का असर रह सकता है।

अप्रैल में ऐसा रहा अब तक का मौसम

अप्रैल के पहले, दूसरे और तीसरे सप्ताह में तेज गर्मी और बारिश का दौर बना रहा। पहले सप्ताह में सभी संभागों में सामान्य से 2-3 डिग्री ज्यादा 21-24 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, दिन में पश्चिमी गर्म हवाओं के कारण अधिकतम तापमान इंदौर, सागर और नर्मदापुरम संभागों में सामान्य से ज्यादा 39 से 44 डिग्री तक पहुंच गया। उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर समेत बाकी संभागों में यह 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पहले सप्ताह रतलाम में लू चल चुकी है। वहीं, बाकी शहरों में गर्म हवाओं से गर्मी बढ़ी रही।

दूसरे सप्ताह में पूरे प्रदेश में तेज आंधी, बारिश, ओले और गरज-चमक की स्थिति बनी रही। प्रदेश के 80 प्रतिशत हिस्से में बारिश हुई। दूसरी ओर, कुछ जिलों में गर्मी का असर भी रहा।

तीसरे सप्ताह में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के जोर पकड़ने के साथ इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, नर्मदापुरम संभागों में न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। वहीं, पूरे प्रदेश में दिन में अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा रहा। कई जिलों में लू भी चली।